



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271180  
CG-DL-E-23032026-271180

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]  
No. 59]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947  
NEW DELHI TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026  
(अंतिम जांच परिणाम)

मामला सं. AD (SSR)- 01/2025

**विषय:** सऊदी अरब से उद्भूत या वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा जांच।

**फा.सं. 07/03/2025-डीजीटीआर.**—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, यथासंशोधित (जिसे आगे अधिनियम भी कहा जाएगा), तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, यथासंशोधित (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा जाएगा), पर विचार करते हुए;

## क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" भी कहा जाएगा) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, यथासंशोधित (जिसे आगे अधिनियम भी कहा जाएगा), तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, यथासंशोधित (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा जाएगा) के अनुसार फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल (जिसे आगे "एफएसपी" या "विचाराधीन उत्पाद" या "विषय वस्तु" भी कहा जाएगा) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा प्रारंभ करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक ने सिंगापुर, सऊदी अरब और UAE से आयातों पर शुल्कों की समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तथापि, प्रारंभ के समय, प्राधिकारी ने नोट किया कि सिंगापुर से आयातों पर शुल्कों की समीक्षा का अनुरोध करने वाला आवेदन, व्यापार सूचना सं. 2/2017, दिनांक 12 दिसंबर 2017 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया कि UAE में विचाराधीन उत्पाद का कोई ज्ञात उत्पादक नहीं है जो भारत को विषय वस्तु का निर्यात कर सके। इस प्रकार, प्राधिकारी ने सिंगापुर और UAE से आयातों पर शुल्कों की समीक्षा प्रारंभ नहीं की। तदनुसार, वर्तमान समीक्षा सऊदी अरब (जिसे आगे "विषय देश" भी कहा जाएगा) से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में है।

2. सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से उद्भूत या वहां से निर्यातित विषय वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 6/20/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 सितंबर 2019 के माध्यम से प्रारंभ की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/20/2019-डीजीटीआर, दिनांक 1 सितंबर 2020 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और सऊदी अरब तथा UAE से विषय वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 20/2021-सीमा शुल्क (ADD), दिनांक 5 अप्रैल 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया।

3. अधिनियम की धारा 9A(5) के तहत, नियमावली के नियम 23(1B) के साथ पठित, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक पहले रद्द न किया जाए, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभाव से हट जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या प्रवृत्त शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. आवेदक ने दिनांक 29 जनवरी 2025 को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की सूर्यास्त समीक्षा प्रारंभ करने और फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की मांग की गई। अनुरोध इस आधार पर था कि शुल्क की समाप्ति से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है।

5. पाटन और क्षति की निरंतरता की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन को दृष्टिगत रखते हुए, अधिनियम की धारा 9A(5), नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 07/03/2025-डीजीटीआर, दिनांक 18 मार्च 2025 के माध्यम से सऊदी अरब से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा प्रारंभ करने वाली एक सार्वजनिक सूचना जारी की। प्राधिकारी ने पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा प्रारंभ की ताकि यह जांच की जा सके कि क्या सऊदी अरब से विषय वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

## ख. प्रक्रिया

6. जांच के संदर्भ में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

### 6.1 प्रारंभ

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच प्रारंभ करने से पहले भारत में विषय देश के दूतावास को वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने 18 मार्च 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें विषय देश से विषय वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा प्रारंभ की गई।

ग. प्राधिकारी ने भारत में उसके दूतावास के माध्यम से विषय देश की सरकार, विषय देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों पर, प्रारंभ अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में ज्ञात कराने का अनुरोध किया।

## 6.2 आवेदन का अगोपनीय संस्करण परिचालित करना

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में विषय देश के दूतावास के माध्यम से विषय देश की सरकार को आवेदन का एक अगोपनीय संस्करण प्रदान किया। आवेदन का अगोपनीय संस्करण जहां अनुरोध किया गया, वहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया गया।

## 6.3 विषय देश के निर्यातकों की भागीदारी

ङ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों पर विषय देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को निर्यातकों की प्रश्नावली भेजी और उनसे विस्तारित समय-सीमा तक अपने विचार लिखित रूप में ज्ञात कराने का अनुरोध किया।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातकों की प्रश्नावली भेजी:

1. सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
2. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एसएबीआईसी), सऊदी अरब
3. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक पीटीई. लि. (एसएपीपीएल), सिंगापुर
4. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (डीसीआईपीएल) दुबई शाखा, UAE
5. डाउ सऊदी अरबिया मार्केटिंग बी.वी., (डीएसएपीएम बीवी), नीदरलैंड
6. डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

छ. भारत में विषय देश के दूतावास से अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का जवाब देने की सलाह दें।

ज. विषय जांच के प्रारंभ के जवाब में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल करके जवाब दिया:

1. सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
2. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एसएबीआईसी), सऊदी अरब
3. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक पीटीई. लि. (एसएपीपीएल), सिंगापुर
4. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (डीसीआईपीएल) दुबई शाखा, UAE
5. डाउ सऊदी अरबिया मार्केटिंग बी.वी., (डीएसएपीएम बीवी), नीदरलैंड
6. डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
7. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

## 6.4 आयातकों/उपयोगकर्ताओं की भागीदारी

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगने के लिए भारत में विषय वस्तु के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आयातकों और उपयोगकर्ताओं की प्रश्नावली भेजी:

1. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2. शीला फोम लि. (एसएफएल)
3. तिरुपति फोम लि.

4. एम.एच. पॉलीमर्स लि.
  5. टोयोटा त्सुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  6. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, भारत (डीसीआईपीएल)
- ज. विषय जांच प्रारंभ अधिसूचना के जवाब में, निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल करके जवाब दिया:
1. शीला फोम लिमिटेड (एसएफएल)
  2. एक्सपैंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
- ट. प्रारंभ अधिसूचना और आवेदन का अगोपनीय संस्करण इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन को भी भेजा गया। एसोसिएशन ने समीक्षा के दौरान प्रस्तुतियां कीं।
- ठ. प्रारंभ अधिसूचना और आवेदन का अगोपनीय संस्करण रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भी भेजा गया। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।
- ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपनी प्रस्तुतियों का अगोपनीय संस्करण ईमेल करें।
- ढ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया।
- ण. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए विषय वस्तु के आयातों का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए लेनदेनों की उचित जांच के बाद डीजी सिस्टम्स डेटा पर निर्भरता रखी है।
- त. भारत में विषय वस्तु के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम लागत पर आधारित क्षतिरहित कीमत (एनआईपी), जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली की अनुसूची III के आधार पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार है, यह पता लगाने के लिए तैयार की गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### 6.5 जांच अवधि और क्षति अवधि

- थ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि को कवर करती है।

#### 6.6 आगे की प्रक्रिया

- द. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 3 दिसंबर 2025 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों की लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के बाद प्रतिउत्तर प्रस्तुतियां दाखिल करने का अनुरोध किया गया।
- ध. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी गई हैं, इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से ध्यान में लिया गया है।
- न. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटीकरण विवरण 5 मार्च 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जांच प्रासंगिक समझे जाने की सीमा तक की है। कोई भी प्रस्तुति जो पिछली प्रस्तुतियों की मात्रा पुनरावृत्ति थी और जिसे प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से परखा जा चुका था, संक्षिप्तता के लिए नहीं दोहराई गई है।

- प. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित था, वहां गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
- फ. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार किया या अन्यथा आवश्यक जानकारी नहीं दी, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डाली, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- ब. प्राधिकारी ने जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया, जो जहां तक संभव हो इस प्रकटीकरण विवरण का आधार बनती है और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत डेटा/दस्तावेजों को उस सीमा तक सत्यापित किया जिसे प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया।
- भ. इस अधिसूचना में '\*\*\*' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी को दर्शाता है जिसे नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा उसी रूप में माना गया है।
- म. विषय जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर: 1 अमरीकी डॉलर = ₹ 84.27

## ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

### 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।

- क. डबल मेटल साइनाइड (डीएमसी) उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी और घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (केओएच) आधारित उत्प्रेरक विधि से उत्पादित उत्पाद तुलनीय नहीं हैं।
- ख. डीएमसी आधारित एफएसपी उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों में पसंद की जाती है क्योंकि यह आणविक भार वितरण को संकरा करती है, उप-उत्पादों के निर्माण को कम करती है, उत्पाद शुद्धता में सुधार करती है, उच्च प्राथमिक हाइड्रॉक्सिल सामग्री और बेहतर प्रतिक्रियाशीलता को सक्षम करती है।
- ग. केओएच प्रौद्योगिकी से उत्पादित उत्पाद में अधिक पोटेशियम अवशेष होता है जो इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा पॉलीमर पॉलिओल उत्पादन में अनुपयोगी बना देता है। इसके विपरीत, डीएमसी प्रौद्योगिकी से उत्पादित एफएसपी उपयोगकर्ताओं की प्रक्रिया के अनुरूप है।
- घ. उपयोगकर्ता पॉलीमर पॉलिओल के उत्पादन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तु का उपयोग करने में असमर्थ हैं।
- ङ. प्रयोक्ता उद्योग घरेलू एफएसपी की तुलना में एफएसपी के आयात पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें अपेक्षित गुणवत्ता का अभाव है, जिससे डाउनस्ट्रीम और निर्यात-मुखी क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित हो जाती है।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता खराब है। जबकि बड़े निर्माता कभी-कभी घरेलू उत्पाद में दोषों को कम कर सकते हैं, अधिकांश डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता जो एमएसएमई हैं, के पास इन विसंगतियों को ठीक करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है।
- छ. DMC-आधारित FSP विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए या वर्तमान समीक्षा जांच में DMC-आधारित FSP के लिए एक अलग PCN बनाना चाहिए।
- ज. उत्पाद का दायरा 3000 आणविक भार वाले एफएसपी तक सीमित होना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग 3000 से अधिक आणविक भार वाले एफएसपी का उत्पादन नहीं करता है।
- झ. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 3000 से कम और 4000 से अधिक आणविक भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित पीयूसी के भीतर नहीं आते हैं और इसलिए इसे वर्तमान

जांच के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। इस तरह के ग्रेडों को शामिल करना, उनकी विशिष्ट तकनीकी विशेषताओं, अनुप्रयोगों और वाणिज्यिक बाजारों के बावजूद, प्राधिकरण की उत्पाद परिभाषा के साथ असंगत होगा और अनुचित रूप से जांच को इसके कानूनी रूप से अनुमेय दायरे से परे व्यापक करेगा।

## 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

### 8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद 3000-4000 आण्विक भार वाला फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल है।
- ख. उत्पाद का उपयोग फोम के निर्माण में किया जाता है जो मुख्य रूप से गद्दों, असबाब, तकियों, बोल्स्टर, परिवहन सीटों और पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है। फरवरी 2022 से पहले, उत्पाद को टैरिफ आइटम '3907 20' के तहत आयात किया गया था और उसके बाद, इसे टैरिफ आइटम '3907 29 10' और '3907 29 90' के तहत आयात किया गया था।
- घ. विषय वस्तुओं का उत्पादन KOH या DMC तकनीक का उपयोग करके किया जा सकता है। जबकि आवेदक ने KOH तकनीक का उपयोग किया है, विषय देशों के उत्पादकों ने दोनों तकनीकों का उपयोग किया है।
- ङ. केओएच तकनीक या डीएमसी तकनीक का उपयोग करके उत्पादित एफएसपी तुलनीय है और इसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और उत्पाद प्रक्रिया में कोई बड़ा अंतर नहीं है।
- च. दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित अंतिम उत्पाद की तकनीकी और रासायनिक विशेषताएं समान हैं, सिवाय पोटेशियम अवशेष के।

पैरामीटर	केओएच-उत्प्रेरित पॉलिओल	डीएमसी-उत्प्रेरित पॉलिओल	टिप्पणी
आण्विक भार	3000-4000	3000-4000	समान
हाइड्रॉक्सिल संख्या (मि.ग्रा. केओएच/ग्रा.)	~48-56	~48-56	समान
विस्कोसिटी @ 25°C (cP)	500-700	400-600	समान
कार्यक्षमता	3 (ट्रायोल)	3 (ट्रायोल)	समान
पोटेशियम अवशेष	5-10 ppm (निराकरण के बाद)	<1 ppm	भिन्न
रूप	साफ तरल	साफ तरल	समान

छ. घरेलू उद्योग देश के सभी प्रमुख उपभोक्ताओं को नियमित रूप से विषय वस्तु की आपूर्ति कर रहा है जो दर्शाता है कि उपयोगकर्ता केओएच और डीएमसी प्रौद्योगिकी दोनों से उत्पादित उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं।

Name of customer	2021-22	2022-23	2023-24	POI
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

- ज. विश्व स्तर पर, विषय देशों में उत्पादकों सहित सभी उत्पादक KOH तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जबकि कुछ उत्पादकों ने डीएमसी प्रौद्योगिकी के लिए उत्पादन लाइनें जोड़ी हैं, ऐसे उत्पादकों ने केओएच प्रौद्योगिकी के लिए उत्पादन लाइनों को बंद नहीं किया है।
- झ. डीएमसी मार्ग से उत्पादित एफएसपी की गुणवत्ता बेहतर होने के दावे के विपरीत, आयातित एफएसपी की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमत से कम है।
- ञ. प्राधिकारी ने पिछली जांच में निर्धारित किया था कि दोनों प्रौद्योगिकियों से उत्पादित उत्पाद ग्राहकों द्वारा परस्पर उपयोग किए जाते थे।
- ट. इस दावे के विपरीत कि विषय वस्तु का उपयोग पॉलीमर पॉलिओल के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता, आवेदक स्वयं स्व-उत्पादित एफएसपी का उपयोग पॉलीमर पॉलिओल के उत्पादन के लिए कर रहा है जो बाजार में बेचा जाता है।
- ठ. EMPEYOL F3502 विचाराधीन उत्पाद का ब्रांड नाम है, जिसके लिए आवेदक ने तकनीकी डेटा शीट प्रदान की है। उत्पाद "पॉलीथर पॉलीओल्स" नामक उत्पादों के बड़े वर्ग के अंतर्गत आता है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

### 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच के प्रारंभ के समय, प्राधिकारी ने निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना था जो मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में परिभाषित के समान था।

"ix. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल है। विषय उत्पाद 3000-4000 के आण्विक भार का एक स्पष्ट श्यान तरल बहुलक है, जो प्रोपलीन ऑक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड के एक ट्रायोल चैन स्टार्टर के साथ बहुलकीकरण द्वारा निर्मित होता है। यह एक पॉलीएथर है और उत्प्रेरकों और एडिटिव्स के साथ प्रतिक्रिया करने पर पॉलीयूरेथेन फोम उत्पन्न करता है जिसका उपयोग असबाब, गद्दों, तकियों, बोल्स्टर, परिवहन सीटों और पैकेजिंग में किया जाता है। फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल को टैंकरों में ले जाया जाता है या स्टील ड्रम में संग्रहीत किया जाता है (जिसे आगे 'विषय वस्तु' भी कहा जाएगा)।"

x. विषय वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में "प्लास्टिक और उसके वस्तुओं" श्रेणी के तहत और आगे भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 3907 20 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अलग-अलग आईएचसीएचएस को उद्धृत किया जा सकता है, उत्पाद विवरण को सीएचआईएसएस पर प्राथमिक माना जाता है क्योंकि यह सांकेतिक है।

10. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि डबल मेटल साइनाइड (डीएमसी) उत्प्रेरक तकनीक एक आधुनिक और उन्नत प्रक्रिया है और इस तकनीक का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद को केओएच-आधारित विधि पर प्राथमिकता दी जाती है।

यह दावा किया गया है कि डीएमसी आधारित एफएसपी को इसके उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों और उप-उत्पादों के कम निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि वे अपने खराब प्रदर्शन के कारण घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए KOH-आधारित FSP का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

11. इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि किसी भी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है और उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि किसी भी प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया में कोई बड़ा अंतर नहीं है। जबकि उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक जैसे इनपुट भिन्न हो सकते हैं, प्रमुख कच्चे माल, यानी प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, समान हैं। पोटेशियम अवशेषों के संबंध को छोड़कर, केओएच या डीएमसी मार्ग का उपयोग करके उत्पादित एफएसपी की तकनीकी विशेषताएं भी काफी हद तक समान हैं। इसके अलावा, भारत के फोम निर्माताओं द्वारा फिलर्स के उपयोग से पोटेशियम अवशेषों के अंतर को आसानी से ऑफसेट किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि वह देश के सभी प्रमुख फोम उत्पादकों को नियमित रूप से अपने उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया है। वास्तव में, आवेदक स्वयं डाउनस्ट्रीम उत्पाद बनाने के लिए KOH-आधारित FSP का उपयोग कर रहा है।

12. KOH और DMC तकनीक के बीच अंतर के बारे में इसी तरह के तर्क मूल जांच में भी इच्छुक पार्टियों द्वारा दिए गए हैं। हालांकि, प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्ष में ऐसे दावों को खारिज कर दिया और निर्धारित किया कि किसी भी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित उत्पादों का उपयोग ग्राहकों द्वारा परस्पर विनिमय के रूप में किया गया था।

13. प्राधिकरण ने अन्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की है। उठाए गए उपरोक्त तर्कों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि वर्तमान जांच विषय देश से आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की एक सूर्यास्त समीक्षा है। प्राधिकरण ने पहले ही जांच की है और निर्धारित किया है कि मूल जांच में घरेलू उद्योग और विषय देश के निर्माता द्वारा उत्पादित उत्पादों में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकरण का कहना है कि यह स्थिति आज भी बनी हुई है।

14. दोनों प्रौद्योगिकियों से उत्पादित एफएसपी के तकनीकी गुणों में अंतर के विरुद्ध उठाए गए तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों मार्गों की उत्पादन प्रक्रिया समान है और उपयोग किए गए कच्चे माल भी समान हैं। एकमात्र अंतर उपयोग किए गए उत्प्रेरकों में है। अंतिम उत्पाद के तकनीकी और भौतिक गुण समान श्रेणी में हैं।

15. इसके अलावा, कुछ इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वे केओएच प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद की खराब गुणवत्ता के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद का उपयोग करने में असमर्थ हैं, जबकि डीएमसी आधारित उत्पाद उच्च गुणवत्ता का है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग नियमित रूप से अपने ग्राहकों को उत्पाद की आपूर्ति कर रहा है, जिन्होंने KOH तकनीक का उपयोग करके उत्पादित अपने उत्पाद को खरीदना जारी रखा है। इस प्रकार, ऐसा मामला नहीं है कि उपयोगकर्ताओं ने उत्पाद के घटिया होने के कारण घरेलू उद्योग से उत्पाद खरीदना बंद कर दिया है।

16. इसके अलावा, डीएमसी आधारित प्रौद्योगिकी से उत्पादित होने का दावा करने वाली आयातित विषय वस्तु की कीमत, केओएच आधारित प्रौद्योगिकी पर आधारित घरेलू रूप से उत्पादित एफएसपी से कम है।

17. इस प्रकार, प्राधिकरण नोट करता है कि विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के उपयोग से अंतिम उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित विषय वस्तुओं का उपयोग एक ही अनुप्रयोग के लिए और एक ही तरीके से किया जाता है, और विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित अंतिम उत्पाद की विशेषताएं समान होती हैं। उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है और उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा एक दूसरे के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। वास्तव में, प्राधिकरण ने पिछली जांच में माना है कि विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग अंतिम उत्पाद को अलग नहीं करता है, अगर इस तरह की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पाद विशेषताओं और अंतिम उपयोग में अंतर नहीं होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि डीएमसी-आधारित एफएसपी और केओएच-आधारित एफएसपी के बीच कोई अंतर नहीं है, और दोनों एक दूसरे के लिए लेख की तरह हैं। इस प्रकार, DMC-आधारित FSP को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

18. कुछ इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि उत्पाद का दायरा केवल 3000 के आणविक भार के साथ एफएसपी तक सीमित होना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग इससे अधिक आणविक भार वाले उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकता है। तकनीकी डेटा शीट और नमूना बिक्री चालान के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि घरेलू

उद्योग ने 3000 से अधिक आणविक भार वाले उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है। इस प्रकार, इस संबंध में अन्य पक्षों का तर्क अमान्य है।

19. इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित के समान ही रहता है।

20. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन कार्यप्रणाली के निर्धारण के संबंध में अपनी प्रस्तुतियां दाखिल करने का अवसर दिया।

21. कुछ इच्छुक पार्टियों ने अनुरोध किया कि यदि डीएमसी-आधारित एफएसपी को बाहर नहीं रखा जाता है, तो डीएमसी-आधारित उत्पादों के लिए एक अलग पीसीएन बनाया जाना चाहिए। प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियां यह प्रदर्शित करने में विफल रही हैं कि डीएमसी-आधारित एफएसपी और केओएच-आधारित एफएसपी में लागत और परिणामी कीमतों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसलिए, वर्तमान जांच में डीएमसी-आधारित एफएसपी के लिए पीसीएन पद्धति के सृजन की कोई आवश्यकता नहीं है।

22. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में विषय देश से आयातित उत्पाद के बराबर है। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से विनिमेय हैं। तदनुसार, प्राधिकरण का यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमों के नियम 2(डी) के अनुसार विषय देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

### घ. घरेलू उद्योग का दायरा और अधिकार

1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और अधिकार के संबंध में कोई प्रस्तुति नहीं की है।

2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग के दायरे और अधिकार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

- आवेदक देश में विषय वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, और इस प्रकार कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(b) के तहत घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र है।

### 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

25. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(b) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(b) 'घरेलू उद्योग' का अर्थ है समान वस्तु के निर्माण में लगे घरेलू उत्पादक समग्र रूप से और उससे संबद्ध कोई गतिविधि या वे उत्पादक जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, सिवाय जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द को शेष उत्पादकों के संदर्भ में माना जा सकता है।"

26. वर्तमान आवेदन मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक भारत में विषय वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारत में विषय वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है।

27. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विषय देश से आयातित विषय वस्तु का समान वस्तु है।

28. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक ने जांच अवधि के दौरान विषय देश से विषय वस्तु का आयात नहीं किया है। आवेदक विषय देश में विषय वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में विषय वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(b) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अर्थ में अधिकार की आवश्यकता को पूरा करता है।

### ड. गोपनीयता

1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।

- घरेलू उद्योग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए क्षमता और उत्पादन डेटा के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो पहले प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों में प्रकट किया गया था।

- ख. आवेदक ने एनआईपी और शुद्ध बिक्री प्राप्ति के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो व्यापार नोटिस 10/2018 का उल्लंघन है। प्राधिकरण को स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम डीए में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किए बिना गोपनीयता के दावे को स्वचालित रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए था; एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम डीए में सीईएसटीएटी; और ईसी में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय - चीन से कुछ लौह या स्टील फास्टरों।
- ग. निर्यातक ने पूर्ण अनुपालन और पारदर्शिता की दृष्टि से सभी तृतीय देश की बिक्री का विवरण प्रदान किया है। तृतीय देश की बिक्री के विवरण का प्रकटीकरण निर्यातक के हितों के लिए हानिकारक होगा।
- घ. निर्यातक ने संबंधित वस्तुओं की बिक्री में शामिल सभी सहयोगियों के नाम प्रदान किए हैं और भारत में संबंधित वस्तुओं की बिक्री में कोई अन्य सहयोगी शामिल नहीं है।

## 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।

- क. एसएबीआईसी सामान्य मूल्य की गणना के लिए उचित तृतीय देश और उसके चयन के आधार के संबंध में विवरण का अगोपनीय सारांश प्रदान करने में विफल रहा है।
- ख. घरेलू उद्योग ने निर्यातकों की पूरी तृतीय देश की बिक्री का खुलासा नहीं मांगा है, लेकिन कम से कम निर्यातक को यह बताना चाहिए कि क्या वह तृतीय देश की बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा कर रहा है।
- ग. एसएबीआईसी भारत में स्थित सहयोगियों के विवरण और ऐसी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यकलापों का खुलासा करने में विफल रहा है। ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।
- घ. गोपनीयता के दावों के संबंध में इच्छुक पक्षों के तर्क अत्यधिक देर से हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- ङ. एकल आवेदक के रूप में, घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय संस्करण में क्षमता और उत्पादन के आंकड़े रूझान के रूप में प्रदान किए हैं।
- च. घरेलू उद्योग की गैर-हानिकारक कीमत अत्यधिक गोपनीय है, और ग्राहकों के साथ अपनी बातचीत में घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकती है। इस प्रकार, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है।

## 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

32. जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"गोपनीय जानकारी: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर नामित प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी को उसकी गोपनीयता के रूप में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पक्ष को ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) नामित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाली पार्टियों को गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसी पार्टी नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकती है कि संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि नामित प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

33. ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक हो, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पक्षों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी के पर्याप्त गैर-गोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि सभी इच्छुक पार्टियों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है।

## च. विविध प्रस्तुतियां

### 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियां की गई हैं।

- क. याचिका एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 5 और एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है क्योंकि इसमें कथित डंपिंग, चोट और कारण लिंक के संबंध में सबूतों का अभाव है। आवेदक ने उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जो अनुलग्नक I के पैरा 1 के विपरीत है और केवल समुद्री माल दुलाई के लिए समायोजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया है। कानूनी प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के आधार पर एक पहल शुरू से ही शून्य है और इस तरह की जांच को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, जैसा कि अध्यक्ष-सह-एमडी, कोल इंडिया और अन्य बनाम अनंत साहा और अन्य, (2011) 5 एससीसी 142 में आयोजित किया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग लंबे समय से पाटनरोधी शुल्कों का लाभार्थी रहा है, जो विभिन्न देशों से एफएसपी के आयात को प्रतिबंधित करता है और इसमें कुछ मामलों में आवेदन वापस लेना शामिल है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को 2001 से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है।
- ग. कर्तव्यों की लंबी अवधि के बावजूद, घरेलू उद्योग उत्पादन, प्रौद्योगिकी और क्षमता में सुधार प्रदर्शित करने में विफल रहा है, और लागत को कम करने, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में विफल रहा है।
- घ. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात डेटा अविश्वसनीय है क्योंकि यह मूल अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आयात डेटा के साथ संरेखित नहीं है। यहां तक कि अगर डीजीसीआईएंडएस से आयात के आधार पर जांच शुरू की गई थी, तो आवेदन में कमी थी और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था और यह वर्तमान कार्यवाही की तुच्छता और आंतरिक विसंगतियों को उजागर करता है।
- ङ. एसोसिएशन की सदस्यता को सार्वजनिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, और आवेदक द्वारा एसोसिएशन की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई भी प्रयास अनुचित है, यह देखते हुए कि आवेदक स्वयं एसोसिएशन का सदस्य है।
- च. प्राधिकरण को उपयोगकर्ता उद्योग को उस प्रारूप और तरीके से आयात डेटा प्रदान करना चाहिए जिसमें इसे रिकॉर्ड पर रखा गया था। इस संबंध में विदेशी सजावट प्राइवेट लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण पर भरोसा रखा गया था।
- छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह आवेदक द्वारा दावा किए गए अतिरंजित मार्जिन के विरुद्ध क्षति निर्धारण के लिए डीजीसीआई एंड एस डेटा का उपयोग करे।
- ज. डीआई ने वास्तविक घर-बाजार डेटा, तीसरे देश की कीमतों, या उचित रूप से समर्थित निर्मित सामान्य मूल्य प्रस्तुत नहीं किया। डीआई ने एक निर्मित एनवी के निर्माण के लिए केवल उत्पादन की अपनी भारतीय लागत पर भरोसा किया - एक विधि जो कानून द्वारा समर्थित नहीं है।
- झ. तीसरे देशों को निर्यात का लेन-देन-वार विवरण गोपनीय है और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के संदर्भ में इसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

### 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियां की गई हैं।

- क. व्यापार उपाय जांच के दुरुपयोग के दावे निराधार हैं, क्योंकि विदेशी उत्पादक ही उचित बाजार का दुरुपयोग कर रहे हैं।

- ख. अन्य इच्छुक पार्टियों के तर्क के विपरीत, प्राधिकरण ने पाया कि विषय आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है और पिछली जांच में कर्तव्यों को जारी रखने की आवश्यकता थी, सिवाय इसके कि आवेदक ने डंपिंग के खिलाफ अस्थायी राहत पर विचार करते हुए अपना आवेदन वापस ले लिया हो।
- ग. आवेदक ने तीसरे पक्ष से प्राप्त आयात पर भरोसा किया है, जबकि प्राधिकरण डीजीसीआईएंडएस डेटा पर निर्भर करता है, जिसके कारण आयात की मात्रा में अंतर हो सकता है।
- घ. एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की सूची प्रदान नहीं की है, या यह प्रदर्शित नहीं किया है कि इसके कौन से सदस्य उपायों से प्रभावित होंगे। इसलिए, इसने एक इच्छुक पार्टी के रूप में अपनी स्थिति का प्रदर्शन नहीं किया है। एसोसिएशन को यह भी प्रदर्शित करना होगा कि वह भाग लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत था।
- ङ. आवेदक ने आवेदन दाखिल के समय उचित रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर विषय देश के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य प्रदान किया।

### 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

36. इस निवेदन के संबंध में कि याचिका एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 5 और एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है क्योंकि इसमें कथित डंपिंग, चोट और कारण लिंक के संबंध में सबूतों का अभाव है, प्राधिकरण ने नोट किया कि वर्तमान समीक्षा प्रदान किए गए सबूतों की प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर शुरू की गई थी और आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता पर खुद को विधिवत संतुष्ट करती थी। दीक्षा के समय इसके लिए यथोचित रूप से उपलब्ध है।

37. इस निवेदन के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का दुरुपयोग कर रहा है और पिछले दो दशकों से व्यापार उपचारात्मक जांच का लाभार्थी रहा है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि सभी जांच सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच के आधार पर की गई हैं और डंपिंग की जांच के बाद ही कर्तव्यों को लागू करने/जारी रखने की सिफारिश की गई है। चोट और कारण लिंक, जहां भी प्रासंगिक हो।

38. कुछ इच्छुक पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कर्तव्यों की लंबी अवधि के बावजूद, घरेलू उद्योग उत्पादन में सुधार, क्षमताओं में वृद्धि और लागत दक्षता प्रदर्शित करने में विफल रहा है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच में, प्राधिकरण को यह जांचना अपेक्षित है कि विचाराधीन उत्पाद को देश में कहां डंप किया जा रहा है और इस तरह के डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। तथ्य यह है कि निर्यातक देश में वस्तु वस्तुओं को डंप कर रहे हैं, यह एक भौतिक तथ्य है, भले ही उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की हो या नहीं।

इस निवेदन के संबंध में कि प्राधिकरण ने उपयोगकर्ता उद्योग को निर्धारित प्रारूप और तरीके से आयात डेटा उपलब्ध नहीं कराया है, प्राधिकरण नोट करता है कि डीजीसीआईएंडएस लेन-देन के अनुसार आयात डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और इसे वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत किसी भी पक्ष के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।

39. कुछ इच्छुक पार्टियों ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उपयोग किया गया डेटा विश्वसनीय नहीं है और इस प्रकार, मार्जिन के बड़े हुए दावे हुए हैं। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक ने दायर आवेदन में बाजार स्रोतों से प्राप्त आयात डेटा पर भरोसा किया है। हालांकि, प्राधिकरण ने इस जांच के उद्देश्य के लिए डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात डेटा पर भरोसा किया है। इसके अलावा, सहयोगी निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित होगा और प्राधिकरण द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा। तदनुसार, आवेदक द्वारा अपने आवेदन में उपयोग किए गए आयात डेटा की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण नहीं है।

### छ. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

#### 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।

- क. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह सदारा द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की गणना करे, न कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर, जो टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के साथ असंगत हैं।

- ख. डीआई के दावा किए गए समायोजन - जैसे कि समुद्री माल ढुलाई, बीमा और कमीशन के लिए - किसी भी अंतर्निहित सबूत के साथ नहीं हैं। एसएबीआईसी और एसएपीएल ने अत्यधिक सावधानी के रूप में तीसरे देश के निर्यात के बारे में जानकारी प्रदान की। सभी तीसरे देशों को लेन-देन-वार निर्यात विवरण प्रदान किया गया है।
- ग. सदर द्वारा रिपोर्ट की गई लागतों की अवहेलना करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि प्राधिकरण ने पिछली जांचों (जैसे एफएसपी और टीडीआई) में पहले ही स्थापित कर दिया है कि एसएबीआईसी से सदारा की खरीद हाथ की लंबाई पर है।
- घ. कई डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय रिपोर्टों ने माना है कि निर्यातक के रिकॉर्ड में दर्ज लागतों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
- ङ. यूएस-ओटीसीजी पर आवेदक की निर्भरता गलत है क्योंकि उस जांच में भी, पैनल ने यह निर्धारित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उपयोग की अनुमति नहीं दी थी कि खरीद मूल्य हाथ की लंबाई पर थे या नहीं।
- च. मनाली ने दावा किया है कि सदारा ने दो प्रमुख कच्चे माल प्रोपलीन और एथिलीन को एसएबीआईसी से प्राप्त किया है। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि सदारा ने एसएबीआईसी से इनमें से कोई भी इनपुट नहीं लिया है। तदनुसार, सदर के लिए सामान्य मूल्य की गणना प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दावा किए गए उत्पादन की लागत के आधार पर की जानी चाहिए।
- छ. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सऊदी अरब से आयात की मात्रा 1,11,154 मीट्रिक टन है। तथापि, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार POI के दौरान सदारा (केएसए में एकमात्र उत्पादक) द्वारा वास्तविक निर्यात मात्रा केवल 53314 मीट्रिक टन है। इस प्रकार, निर्यात की मात्रा के साथ-साथ मनाली द्वारा दावा किया गया निर्यात मूल्य गलत और भ्रामक है।
- ज. मनाली द्वारा चित्रित एफएसपी के आयात से संबंधित डेटा गलत है, इसकी पुष्टि आवेदन में डेटा की तुलना और डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए पहले के अंतिम निष्कर्षों से होती है। चीन और थाईलैंड से निर्यात के संबंध में डीजीटीआर द्वारा पहले जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसार, 2021-22 के दौरान एफएसपी की कुल आयात मात्रा 91,155 मीट्रिक टन निर्धारित की गई थी। इसके विपरीत, वर्तमान आवेदन में मनाली ने 161,121 मीट्रिक टन आयात मात्रा का दावा किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मनाली द्वारा प्रस्तुत डेटा गलत है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

## 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

- क. सदारा द्वारा अपने संबंधित पक्षों से खरीदे गए इनपुट की कीमत को तब तक अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जब तक कि निर्माता यह प्रदर्शित नहीं कर सकता कि इस तरह के लेनदेन एक हाथ की लंबाई के आधार पर थे। यदि ऐसी जानकारी उपयुक्त और सटीक पाई जाती है, तो इसका उपयोग निर्यातकों के लिए डंपिंग माजन के निर्धारण के लिए किया जा सकता है।
- ख. यदि निर्यातक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ है कि सहयोगियों से खरीदे गए निवेश बाजार मूल्य के आधार पर थे, तो उत्पादक के लिए उत्पादन की लागत ट्रेड मैप डेटा के आधार पर सऊदी अरब से प्रोपलीन और इथिलीन के निर्यात मूल्य के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
- ग. प्राधिकरण को तीसरे देश के निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य के दावे की जांच करनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे देश को निर्यात की प्रतिनिधि मात्रा और निर्यात व्यापार के सामान्य क्रम में हैं।
- घ. प्राधिकरण को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करना चाहिए, विशेष रूप से संबद्ध पार्टियों से इनपुट की खरीद के संबंध में। यदि ऐसी जानकारी उपयुक्त और सटीक पाई जाती है, तो इसका उपयोग निर्यातकों के लिए डंपिंग माजन के निर्धारण के लिए किया जा सकता है।
- ङ. तथ्य यह है कि प्राधिकारी को पिछली जांचों में पाटन मिला है, यह दर्शाता है कि पाटन डीआई की प्रौद्योगिकी या एकीकरण के स्तर के कारण नहीं है, बल्कि विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के कारण है।

च. इच्छुक पार्टियों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सकारात्मक मूल्य में कटौती के आधार पर डंपिंग का दावा नहीं किया है।

### 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

42. धारा 9A(1)(c) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

"i) निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत समान वस्तु के लिए सामान्य व्यापार के दौरान तुलनीय मूल्य, उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित; या

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं है, या जब विशेष बाजार स्थिति या निर्यातक देश के घरेलू बाजार में कम मात्रा में बिक्री के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती, सामान्य मूल्य होगा:

(क) उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र या उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित जोड़ के साथ-साथ मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत, और लाभ के लिए, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;

43. प्राधिकारी नोट करता है कि निम्नलिखित निर्यातकों ने विषय वस्तु के लिए निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल की हैं:

क. सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब का राज्य

ख. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एसएबीआईसी), सऊदी अरब का राज्य

ग. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक पीटीई. लि. (एसएपीपीएल), सिंगापुर

घ. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (डीसीआईपीएल) दुबई शाखा, UAE

ङ. डाउ सऊदी अरबिया मार्केटिंग बी.वी., (डीएसएपीएम बीवी), नीदरलैंड

च. डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

#### 3.1 सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य

##### सदारा केमिकल्स लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

44. यह नोट किया गया है कि सदारा सऊदी अरब से संबंधित वस्तुओं की घरेलू बिक्री के साथ-साथ डॉव मार्केटिंग, डॉव सिंगापुर, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल जैसी संबंधित संस्थाओं के माध्यम से भारत को निर्यात करता है। सदारा एक सीमित देयता कंपनी है जो सऊदी अरब साम्राज्य के कानूनों के तहत मौजूद है।

45. सदारा द्वारा उत्पादित विषय वस्तु सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एसएबीआईसी) को बेची गई थी, जिसने फिर असंबद्ध ग्राहकों को घरेलू बाजार में उत्पाद को पुनः बेचा। जांच अवधि के दौरान सदारा द्वारा कोई प्रत्यक्ष घरेलू बिक्री नहीं थी।

46. प्राधिकरण ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का डेस्क सत्यापन किया है। प्रतिक्रिया से यह पता चलता है कि जांच की अवधि के दौरान, एसएबीआईसी ने घरेलू बाजार में 26,662.37 मीट्रिक टन सामान बेचा है, जिसका चालान मूल्य घरेलू बाजार में 133.69 मिलियन एसएआर है।

47. सामान्य मूल्य की गणना के लिए, एसएबीआईसी द्वारा असंबंधित ग्राहकों को किए गए सभी घरेलू बिक्री लेनदेन की जांच प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उत्पादन लागत के संदर्भ में की गई थी ताकि यह आकलन किया जा सके कि घरेलू बिक्री व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में थी या नहीं। प्राधिकरण ने विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित किया। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकरण सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार करता है। जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है।

48. व्यापार परीक्षण के सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि सामान्य मूल्य की गणना के लिए पीओआई के दौरान कोई लाभदायक घरेलू बिक्री नहीं होती है। तदनुसार, एसजीए और काल्पनिक लाभ को शामिल करने के बाद प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीयूसी की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है। ऊपर के रूप में निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

सऊदी अरब में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

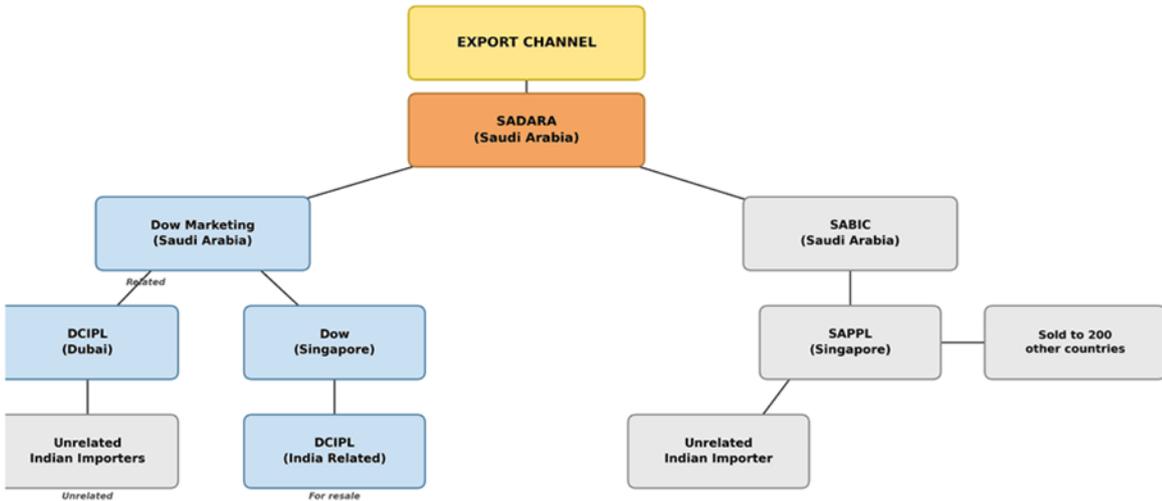
49. सऊदी अरब के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

### 3.2 सऊदी अरब के लिए निर्यात मूल्य

सदारा केमिकल लिमिटेड, सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक पीटीई के लिए निर्यात मूल्य डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा, संयुक्त अरब अमीरात डॉव सऊदी अरब मार्केटिंग बी.वी., नीदरलैंड और डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

50. यह नोट किया गया है कि भारत को निर्यातों के लिए, मेसर्स सदारा विषय वस्तु की पूरी मात्रा डाउ सऊदी अरबिया प्रोडक्ट मार्केटिंग बीवी ("डाउ मार्केटिंग") और सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ("एसएबीआईसी") को बेचती है। भारत को निर्यातों के लिए, डाउ मार्केटिंग डाउ सिंगापुर पर चालान उठाती है जो बदले में डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (डीसीआईपीएल) को बेचती है जिसने उत्पाद का कैप्टिव खपत किया है।

51. निर्यात चैनल को नीचे दिए गए फ्लोचार्ट से समझा जा सकता है।



52. एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए, प्राधिकरण ने उत्पादक (सदारा) के चालान मूल्य से माल ढुलाई, ऋण लागत और कारखाने के बाद के अन्य खर्चों के कारण समायोजन पर विचार किया है। तदनुसार, एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य की गणना की जाती है और नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में उल्लेख किया जाता है।

सऊदी अरब में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

53. सऊदी अरब के अन्य सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे की डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

### 3.3 पाटन मार्जिन

54. ऊपर दिए गए निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

#### पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (अमरीकी डॉलर/एमटी)	निर्यात मूल्य (अमरीकी डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (अमरीकी डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (श्रेणी)
	सऊदी अरब					
1.	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	90-100
2.	कोई भी अन्य	***	***	***	***	100-120

### ज. क्षति का आकलन और कार्य-कारण संबंध

#### 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

- क. जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से आयात की मात्रा में गिरावट आई है जो आवेदक द्वारा किए गए चोट के दावे के विपरीत है। इसके अलावा, जैसे-जैसे मांग बढ़ती रही, मांग को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता हो गई।
- ख. प्राधिकारी को सऊदी अरब से आयातों के लिए कीमत कटौती की गणना लागू पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखने के बाद करनी चाहिए।
- ग. यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समीक्षा अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कथित नुकसान सऊदी अरब से आयात के कारण नहीं है, बल्कि थाईलैंड और चीन से उत्पन्न होने वाले निरंतर कम कीमत वाले आयात के कारण है।
- घ. जांच की अवधि के दौरान, सऊदी अरब के लैंडेड मूल्य में गिरावट आई जबकि घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई, जो घरेलू उद्योग के लैंडेड मूल्य और लागत और बिक्री प्राप्ति के बीच सहसंबंध का अभाव दर्शाता है।
- ङ. विचाराधीन उत्पाद से होने वाले नुकसान कंपनी की समग्र लाभप्रदता में समग्र गिरावट के अनुरूप हैं।
- च. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी की गणना सभी स्रोतों से आयातों पर विचार करने के बाद की जानी चाहिए।
- छ. निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ में लिए गए निर्णय के अनुसार, संभावना विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सूर्यास्त समीक्षा में चोट के खतरे के पैरामीटरों की जांच की जानी अपेक्षित है। वर्तमान मामले में ऐसे पैरामीटरों की जांच नहीं की गई है। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में खतरे के मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है।
- ज. आधार वर्ष के साथ तुलना अनुचित है क्योंकि कोविड से संबंधित व्यवधानों ने मनाली को असामान्य लाभ कमाने में सक्षम बनाया। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट और निवेशक कॉल भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि 2020-21 और 2021-22 असाधारण वर्ष थे, जिनमें रिकॉर्ड बिक्री, लाभप्रदता और बड़े हुए रिटर्न थे।

- झ. मनाली ने दो संयंत्रों में निवेश की योजना बनाई है और पश्चिम भारत में विस्तार को मंजूरी दी है। इसका 0.14:1 का कम ऋण-से-इक्विटी अनुपात मजबूत वित्तीय क्षमता को दर्शाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि पूंजी जुटाने की इसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ञ. घरेलू उद्योग की कीमतें दबी हुई थीं क्योंकि वह अपनी उच्च लागत पूरी करने में असमर्थ था जो उच्च कच्चे माल की कीमतों और आत्म-उत्पन्न आंतरिक व्यवधानों से प्रभावित था।
- ट. सिंगापुर को समीक्षा के दायरे से बाहर करके, आवेदक ने सिंगापुर से महत्वपूर्ण आयात मात्रा की अवहेलना करते हुए चोट विश्लेषण को प्रभावी ढंग से सीमित कर दिया है - जबकि सिंगापुर से महत्वपूर्ण आयात मात्रा की अवहेलना की गई है, जिसकी कीमत प्रस्तावित गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) से कम है। यह चयनात्मक उपचार मौलिक रूप से तथ्यात्मक मैट्रिक्स को विकृत करता है और चोट के एक फुलाए हुए, भ्रामक चित्रण की ओर ले जाता है।
- ठ. प्राधिकरण ने लगातार यह माना है कि सभी संगत स्रोतों से डंप किए गए आयातों की समग्रता के संदर्भ में चोट का आकलन किया जाना चाहिए। किसी अन्य प्रमुख स्रोत से समान रूप से या अधिक हानिकारक आयात की अनदेखी करते हुए एक देश को चुनिंदा रूप से लक्षित करना न केवल चोट के दावे की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, बल्कि कारण लिंक को विश्लेषणात्मक रूप से अनुचित बनाता है।
- ड. घरेलू उद्योग को नुकसान चीन और थाईलैंड के साथ-साथ सिंगापुर से आयात के कारण होता है, और इस तरह की क्षति को सऊदी अरब से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- च. सिंगापुर से महत्वपूर्ण आयात के बावजूद, आवेदक सिंगापुर से शुल्कों को जारी रखने के लिए समय पर आवेदन दायर करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी हुई चोट और गलत कारण लिंक हुआ है। सिंगापुर पर शुल्क न लगाने से व्यापार का डायवर्जन होगा, जिससे शुल्कों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
- छ. वर्तमान एंटी-डंपिंग शुल्कों ने सऊदी अरब से डंपिंग को संबोधित किया है, जबकि चीन और थाईलैंड से महत्वपूर्ण आयात ने नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि आवेदक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है, शुल्कों की प्रत्याशा में ऐसे देशों से आयात में वृद्धि हुई है।
- ज. उत्पादन में जहां 41 अंकों की गिरावट आई है, वहीं निर्यात बिक्री में 88 अंकों की गिरावट आई है। निर्यात बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के बावजूद, आवेदक ने निर्यात बिक्री को कम कर दिया है और आयात मूल्य के अनुरूप चोट की अवधि में इसके निर्यात मूल्य में गिरावट आई है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान, लागत में वृद्धि का दावा किए जाने के बावजूद निर्यात मूल्य स्थिर रहा।
- झ. उत्पादन में गिरावट आयात के कारण नहीं है क्योंकि - (ए) अन्य गैर-विषय वस्तुओं के उत्पादन में भी गिरावट आई है; और (बी) घरेलू उद्योग के पास निर्यात के लिए उत्पादन करने का विकल्प था, लेकिन जानबूझकर उत्पादन को कम करने का विकल्प चुना।
- ञ. प्रमुख वैश्विक कंपनियों की तुलना में घरेलू उद्योग की सीमित उत्पादन क्षमता इसे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने से रोकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति यूनिट लागत अधिक होती है। इसके अलावा, आवेदक पिछड़ा एकीकृत नहीं है और प्रमुख कच्चे माल के लिए अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। अंत में, आवेदक पीओ और ईओ के आपूर्तिकर्ताओं से कुछ दूरी पर स्थित है, जो अप्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।
- ट. आवेदक को चक्रवात मिचौंग के कारण संयंत्र में व्यवधान के कारण विषय वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा, न कि विषय आयात के कारण।
- ठ. आवेदक ने विषय वस्तुओं की कैप्टिव खपत में वृद्धि की है और घरेलू बिक्री को कम किया है।
- ड. मूल्य में कटौती डंपिंग का संकेत नहीं है, बल्कि अप्रचलित प्रौद्योगिकी और पिछड़े एकीकरण की कमी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उच्च लागत के कारण है।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली एफएसपी पुरानी KOH पद्धति के कारण कमतर है, जबकि वैश्विक उत्पादक उन्नत DMC तकनीक का उपयोग करते हैं। परिणामी मूल्य अंतर और चोट गुणवत्ता के मुद्दों और बाजार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है और डंपिंग नहीं करती है।
- ण. एनआईपी के निर्धारण के लिए, आवेदक के उत्पादन की लागत को आवेदकों द्वारा सामना की गई तकनीकी

कठिनाइयों और असाधारण लागतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

- त. एनआईपी का निर्धारण करते समय प्राधिकरण चोट मूल्यांकन अवधि के दौरान आवेदक द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन और क्षमता बाधाओं पर विचार करेगा, और एनआईपी पर विचार करते समय किसी भी असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- थ. चूंकि मनाली ने अपने सहयोगी टीपीएल से पीओ खरीदा है, इसलिए कच्चे माल की वैश्विक कीमतों पर हाथ की लंबाई की कीमत की तुलना के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- द. डीआई की अपनी वार्षिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि चक्रवात मिचौंग के कारण संचालन गंभीर रूप से बाधित हो गया था, जिसने उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया, एक विस्तारित अवधि के लिए उत्पादन रोक दिया, इन्वेंट्री नुकसान का कारण बना, और महत्वपूर्ण मरम्मत व्यय का कारण बना।
- ध. डीआई ने कैप्टिव उपयोग (100 से 364 तक अनुक्रमित वृद्धि) के लिए अपने उत्पादन की अधिक मात्रा को उत्तरोत्तर डायवर्ट किया, जिसने स्वाभाविक रूप से इसकी घरेलू बिक्री को कम कर दिया।
- न. डीआई की खरीद और बिक्री का एक बड़ा हिस्सा संबंधित पार्टियों (कच्चे माल का 28% और पर्याप्त उत्पादन) के साथ था। इस तरह के लेनदेन बाजार की कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं और लागत और लाभप्रदता दोनों को विकृत कर सकते हैं।

## 2. घरेलू उद्योग के विचार

56. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

- क. पूर्ण रूप से और साथ ही भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में चोट की अवधि के दौरान विषय आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयात की मात्रा में गिरावट के बावजूद, आयात की मात्रा महत्वपूर्ण बनी हुई है।
- ख. आयात में वृद्धि की दर ने देश में मांग में वृद्धि की दर को पीछे छोड़ दिया है। वास्तव में, विषय आयात देश में मांग-आपूर के अंतर से अधिक है।
- ग. विषय आयातों की पहुँच कीमत प्रमुख कच्चे माल प्रोपलीन की कीमत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान तेजी से गिरी है।
- घ. क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल पर पहुँच कीमतों का मार्क-अप घटा है।
- ङ. घरेलू उद्योग की लागत में पूर्ण रूप से गिरावट आई है, जिसमें निश्चित लागत और उपयोगिताओं की लागत शामिल है। हालांकि, डंपिंग के कारण, उत्पादन कम हो गया है, और परिणामस्वरूप, प्रति यूनिट लागत अधिक है।
- च. जांच की अवधि के दौरान बिक्री मूल्य और भूमि मूल्य में परिवर्तन को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है और इसे बिक्री की लागत के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
- छ. लैंडेड प्राइस में एंटी-डंपिंग ड्यूटी जोड़ने के बाद भी विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे।
- ज. इस विषय के आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया और कम कर दिया।
- झ. पीओआई के बाद की अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है, जबकि ऐसे आयातों की कीमतों में और गिरावट आई है।
- ञ. कम कीमत वाले विषय आयात की बढ़ती मांग के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में काफी गिरावट आई है। नतीजतन, घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई।
- ट. मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान 50% से कम क्षमता उपयोग पर काम कर रहा था।

- ठ. जबकि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कैपिटल खपत में वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के संबंध में ऐसी खपत क्रमशः 3% और 4% से कम थी।
- ड. जैसे-जैसे इस अवधि के दौरान डंप किए गए आयातों की मांग में वृद्धि हुई, विषय आयातों की बाजार हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम थी।
- ढ. घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण संचय इन्वेंट्री का सामना करना पड़ा, जो चोट की अवधि में 637% बढ़ गया।
- ण. 2022-23 से, घरेलू उद्योग नकद नुकसान सहित महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान उठा रहा है, और इसने अपने निवेश पर नकारात्मक रिटर्न अर्जित किया है।
- त. समग्र रूप से कंपनी के ऋण-इक्विटी अनुपात का संदर्भ उचित नहीं है, क्योंकि चोट विश्लेषण को समान लेख के संदर्भ में आयोजित करने की आवश्यकता होती है।
- थ. इस दावे के विपरीत कि घरेलू उद्योग ने शुल्कों के बावजूद कोई सुधार नहीं दिखाया है, घरेलू उद्योग डंप किए गए आयातों के लगातार हमले के कारण क्षमता या उत्पादन बढ़ाने या नई तकनीक को नियोजित करने में असमर्थ था।
- द. घरेलू उद्योग को अनुचित पाटन की स्थिति में निष्पादन में सुधार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। डंपिंग जो एक अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथा है, और घरेलू उद्योग से ऐसी मूल्य निर्धारण प्रथाओं को ऑफसेट करने के लिए कदम उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
- ध. संबंधित देश में निर्यातकों की मूल जांच में डंपिंग से साक्ष्य डंप करने की प्रवृत्ति है और वर्तमान मामले को डंप करना जारी रखता है।
- न. शुल्क लागू होने के बावजूद विषय आयात की मात्रा में वृद्धि जारी रही है।
- प. जबकि सऊदी अरब से अन्य देशों को निर्यात की मात्रा में मामूली वृद्धि हुई है, भारत को निर्यात में काफी वृद्धि हुई है।
- फ. विषय आयात की कीमत में तेजी से गिरावट जारी है।
- ब. POI के बाद की अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि जारी रही है, जबकि ऐसे आयात की कीमतों में गिरावट आई है।
- भ. विषय आयात उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग की कीमतों को और कम करने की संभावना है।
- म. घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है और यह नाजुक स्थिति में है, जिसके शुल्क की समाप्ति के मामले में इसके और बढ़ने की संभावना है।
- य. बढ़ती मांग को देखते हुए भारत निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है, और शुल्कों की समाप्ति से निर्यात को अपने सभी निर्यात को भारत में मोड़ने की अनुमति मिलेगी।
- र. अनुलग्नक II के पैरा (vii) के प्रावधान (प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ) कर्तव्यों के अभाव में चोट की पुनरावृत्ति के दावे के मामले में लागू होते हैं, जो घरेलू उद्योग का मामला नहीं है।
- ल. घरेलू उद्योग को कोई अन्य कारण नहीं पहुंचा है।
- व. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग पिछड़े एकीकृत नहीं है, आवेदक को पिछड़े एकीकृत संयंत्र न होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसके लिए रिफाइनरी स्थापित करने के लिए बहु-मिलियन निवेश की आवश्यकता होगी, जो व्यवहार्य नहीं है।
- श. घरेलू उद्योग को चोट की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह मौजूद है और उद्योग में निहित कारकों को चोट पहुंचाने के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि यूरोपीय संघ में अपीलिय निकाय द्वारा आयोजित किया गया है - बायोडीजल (अर्जेंटीना), निप्पॉन ज़ीओन कंपनी लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण के मामले में, और विभिन्न जांचों में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है।

- ष. विषय आयात चोट के कारणों में से एक होना चाहिए और चोट का एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए, जैसा कि ईसी - ट्यूब और पाइप, यूएस - हॉट-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स और यूएस - सैल्मन में आयोजित किया गया है।
- स. सिंगापुर से आयात की कीमत विषय आयात की तुलना में अधिक है, और इस तरह के आयातों से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वास्तव में, अगर सऊदी अरब से आयात की कीमत में एंटी-डंपिंग ड्यूटी भी जोड़ दी जाती है, तो कीमत सिंगापुर से आयात की कीमत से कम होती है।
- ह. डंपिंग रोधी शुल्क के बाद सिंगापुर से आयात की कीमत में गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। इस प्रकार, ऐसे आयातों से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत, एंटी-डंपिंग ड्यूटी के लिए लेखांकन के बाद भी, सऊदी अरब से आयात की कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में बहुत कम थी।
- क्ष. चक्रवात के कारण होने वाले शटडाउन के प्रभावों को दूर करने के लिए चोट विश्लेषण में कुल क्षमता को समायोजित करने के बावजूद, घरेलू उद्योग को काफी कम उपयोग की गई क्षमताओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, चूंकि परिवर्तनीय लागत कुल लागत का 80% से अधिक है, इसलिए बंद के कारण बड़ी हुई लागत घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।
- त्र. अनुलग्नक-II के पैरा (vi) के अनुसार पाटनरोधी जांच में अन्य उत्पादों में घरेलू उद्योग का निष्पादन अप्रासंगिक है।
- ज्ञ. विचाराधीन उत्पाद बाजार के लिए मूल्य निर्धारक है और विषय वस्तुओं की बिक्री में गिरावट से सीधे तौर पर गैर-विषय वस्तुओं की बिक्री में गिरावट आती है, जिससे घरेलू उद्योग को समग्र उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- श्र. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री उत्पादन के 2% से कम उत्पादन की तुलना में छिटपुट और नगण्य है। निर्यात की इतनी कम मात्रा के आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। घरेलू उद्योग का प्राथमिक ध्यान घरेलू बाजार पर रहा है।
- कक. कंपनी के समग्र लाभप्रदता में गिरावट का प्रमुख कारण सस्ते आयात में तेज वृद्धि थी जिसने आवेदक की बाजार हिस्सेदारी को कम कर दिया।
- खख. इस दावे के विपरीत कि घरेलू उद्योग ने 2021-22 में असामान्य लाभ अर्जित किया, घरेलू उद्योग ने डंप किए गए आयात से खाली बाजार के कारण मुनाफा कमाया। हालांकि, आयात फिर से शुरू होने के कारण पिछली तिमाही में लाभप्रदता में गिरावट आई।
- गग. अन्य इच्छुक पार्टियों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति की कमी का सामना नहीं करना पड़ा।
- घघ. भले ही घरेलू उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन यह घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले मूल्य दबाव की व्याख्या नहीं करता है।
- ङङ. संबद्ध पार्टी से इनपुट एक हाथ की लंबाई की कीमतों पर खरीदे गए हैं, और प्रोपलीन ऑक्साइड के वैश्विक आयात मूल्यों से कम कीमत है। तथापि, यदि प्राधिकरण को वैश्विक आयात मूल्यों पर विचार करना अधिक उपयुक्त लगता है तो घरेलू उद्योग को कोई आपत्ति नहीं है।
- चच घरेलू उद्योग ने शटडाउन के प्रभाव को कम करने के बाद अपनी क्षमता की जानकारी जमा कर दी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन लागत के हिस्से के रूप में किसी असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय का दावा नहीं किया है।

### 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

57. अनुलग्नक II के साथ पठित एंटीडंपिंग नियमों के नियम 11 में प्रावधान है कि चोट निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को चोट का संकेत दे सकते हैं, "... डंप किए गए आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए। कीमतों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांचना

आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में इस तरह की वस्तु की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य में कटौती की गई है, या क्या इस तरह के आयातों का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी हद तक होता। भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, डंपिंग का परिमाण और मार्जिन आदि पर एंटी-डंपिंग नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार विचार किया गया है।

58. कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि आधार वर्ष के साथ घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की तुलना अनुचित है क्योंकि घरेलू उद्योग इस अवधि के दौरान कोविड से संबंधित व्यवधानों के कारण असामान्य लाभ अर्जित करने में सक्षम था। घरेलू उद्योग ने इस पर विवाद किया है और दावा किया है कि वह केवल इसलिए मुनाफा कमाने में सक्षम था क्योंकि वह डंप किए गए आयात के अभाव में लाभकारी कीमतों पर अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम था। यह ध्यान दिया जाता है कि 2021-22 में, सभी स्रोतों से डंप किए गए आयात की मात्रा चोट की अवधि के दौरान सबसे कम थी। वहीं, पूरी चोट की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री सबसे ज्यादा रही। इसके बाद, चोट की अवधि के दौरान डंप किए गए आयात की मात्रा में वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई। इससे यह स्थापित होता है कि घरेलू उद्योग 2021-22 में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम था जब डंप किए गए आयात ने बाजार को खाली कर दिया और मुनाफा कमाया। हालांकि, इसके बाद इसे नुकसान का सामना करना पड़ा क्योंकि यह अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ रहा है क्योंकि डंप किए गए आयात बाजार के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं।

59. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को नुकसान के संबंध में इच्छुक पक्षों के तर्कों और प्रतिवादों की जांच की है। प्राधिकरण द्वारा किए गए विश्लेषण में इच्छुक पार्टियों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।

### 3.1 डंप किए गए आयात का वॉल्यूम प्रभाव

क) मांग/आभासी खपत का आकलन

60. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग या आभासी खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कैप्टिव खपत को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	99	81	44
विषय देश से आयात	एमटी	31,923	32,882	38,817	54,791
अन्य देशों से आयात	एमटी	67,643	86,793	1,02,260	93,982
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	117	132	133
कैप्टिव खपत सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	100	82	45

विषय देश से आयात	एमटी	31,923	32,882	38,817	54,791
अन्य देशों से आयात	एमटी	67,643	86,793	1,02,260	93,982
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	117	132	133

61. प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में विषय वस्तु की मांग क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी है और जांच अवधि में सबसे अधिक थी।

**ख) विषय देश से आयात की मात्रा**

62. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त लेनदेन-वार आयात डेटा पर निर्भरता रखी है। क्षति अवधि के दौरान विषय देश से आयात की मात्रा निम्नानुसार है:

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
विषय देश से आयात	एमटी	31,923	32,882	38,817	54,791
अन्य देशों से आयात	एमटी	67,643	86,793	1,02,260	93,982
कुल आयात	एमटी	99,566	1,19,675	1,41,076	1,48,773
घरेलू उत्पादन के संबंध में विषय आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	104	143	291
खपत/मांग	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	88	92	130
कुल आयात में हिस्सेदारी	%	32%	27%	28%	37%

63. प्राधिकारी नोट करता है कि:

- विषय देश से आयात की मात्रा क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी है।
- भारत में उत्पादन के सापेक्ष आयात क्षति अवधि में महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हैं और जांच अवधि में सबसे अधिक थे।
- भारत में खपत के सापेक्ष आयात भी क्षति अवधि के दौरान बढ़े हैं।
- जबकि आधार वर्ष में कुल आयातों में विषय आयातों की हिस्सेदारी 32% थी, वही जांच अवधि में 37% तक बढ़ गई है।

64. प्राधिकरण ने आगे कहा है कि भारत में मांग में वृद्धि की दर से बहुत अधिक गति से विषय आयात में वृद्धि हुई है। जबकि चोट की अवधि में मांग में 33% की वृद्धि हुई है, विषय आयात में 72% की वृद्धि हुई है।

### 3.2 डंप किए गए आयात का मूल्य प्रभाव

65. नियमों के अनुलग्नक II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में इसी तरह के उत्पाद की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयात द्वारा एक महत्वपूर्ण मूल्य कटौती की गई है, या क्या इस तरह के आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी हद तक होता।

क) कीमत कटौती

66. कीमत कटौती जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की आयातों की पहुँच कीमत से तुलना करके निर्धारित किया गया है।

विशेष विवरण	इकाई	पीओआई
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
पहुँच कीमत	₹/एमटी	***
कीमत कटौती	₹/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	%	20-30%

67. प्राधिकारी नोट करता है कि विषय आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर हैं। विषय देश से कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ख) घरेलू उद्योग की कच्चे माल लागत पर पहुँच कीमत का डेल्टा

68. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कच्चे माल की लागत में किसी भी महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के बावजूद, लैंडेड कीमत में गिरावट जारी रही है और यह सामग्री की लागत से भी कम है। यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत चोट की अवधि में अपरिवर्तित रही है। हालांकि, इस अवधि के दौरान आयात के लैंडेड प्राइस में 55% की गिरावट आई है। इसके अलावा, जबकि 2021-22 में घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से संबंधित आयात की कीमत लगभग दोगुनी थी, डेल्टा में काफी कमी आई है। 2023-24 और जांच की अवधि में, विषय आयात की कीमत घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से कम थी।

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कच्चे माल की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
पहुँच कीमत	₹/एमटी	2,18,484	1,29,475	1,01,943	98,230
मार्क-अप	₹/एमटी	***	***	***	***
मार्क-अप	%	98%	8%	-6%	-11%

ग) कीमत न्यूनीकरण और हास

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबा रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबाना या मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों में बदलाव की जांच की है।

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	108	98	117
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	69	64	66
पहुँच कीमत	₹/एमटी	2,18,484	1,29,475	1,01,943	98,230
रुझान	सूचकांक	100	59	47	45

70. प्राधिकरण का कहना है कि 2022-23 में बिक्री की लागत में वृद्धि हुई। तथापि, आयातों के विषय मूल्यों में तीव्र गिरावट के कारण घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में गिरावट आई। इसके बाद, घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्यों की लागत और आयातों की उतराई कीमतों में गिरावट आई है। उतार-चढ़ाव वाली कीमतों में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक थी। जांच की अवधि के दौरान, जबकि घरेलू उद्योग की लागत में 17% की वृद्धि हुई है, आयातों के उतार-चढ़ाव वाले मूल्यों में लगातार गिरावट के कारण इसके विक्रय मूल्य में केवल 2% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष के रुझानों की जांच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में 34% की गिरावट आई है, जबकि लैंडेड कीमतों में 55% की गिरावट आई है। इसलिए, यह नोट किया जाता है कि आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है और मूल्य वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा होता।

### 3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

71. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-II में यह अपेक्षा की गई है कि चोट के निर्धारण में संबंधित वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। विषय वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर रिटर्न या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। तदनुसार, चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, बिक्री

72. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोगिता निम्नानुसार थे।

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	100	100	100
उपलब्ध क्षमता	एमटी	***	***	***	***

रुझान	सूचकांक	100	100	100	86
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	99	85	59
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	94	102	65
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	99	81	44
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	37	25	12
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	181	296	364

73. प्राधिकारी नोट करता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही।  
 ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री क्षति अवधि के दौरान घटे हैं।  
 ग. क्षमता उपयोग भी क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से घटा है।

74. यह भी तर्क दिया गया है कि उत्पादन में गिरावट चक्रवात के कारण संयंत्र बंद होने से जुड़ी हुई है। घरेलू उद्योग का कहना है कि संयंत्र के बंद होने के प्रभावों को दूर करने के लिए कुल क्षमता को समायोजित करने के बावजूद उसे महत्वपूर्ण कम उपयोग की गई क्षमताओं का सामना करना पड़ा है। प्राधिकरण का कहना है कि घरेलू उद्योग ने चक्रवात के कारण संयंत्र के बंद होने के प्रभाव को छोड़कर डेटा प्रस्तुत किया है। प्रभाव को छोड़कर भी घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग 50% से कम है। इसलिए, जांच की अवधि में प्रदर्शन में गिरावट को संयंत्र के बंद होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

75. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि विषय वस्तुओं की कैप्टिव खपत में वृद्धि हुई है, हालांकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन मात्रा और घरेलू बिक्री की कुल मात्रा की तुलना में कैप्टिव खपत की मात्रा कम रही है और इसका हिस्सा नगण्य है।

बाजार हिस्सेदारी

76. आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है:

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कैप्टिव खपत को छोड़कर बाजार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	85.14	61.42	33.33

विषय आयात	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	88.11	92.12	129.52
अन्य आयात	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	109.85	114.6	104.9
कैप्टिव खपत सहित बाजार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	85.38	62.06	34.07
विषय आयात	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	88.07	92.04	129.35
अन्य आयात	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	109.73	114.45	104.71

77. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग ने विषय वस्तुओं का कैप्टिव रूप से उपभोग किया है। तदनुसार, बाजार हिस्सेदारी निर्धारित की गई है-

- क) घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत सहित और  
ख) घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत को छोड़कर।

78. प्राधिकरण का कहना है कि चोट की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में अन्य देशों से आयातों के साथ-साथ विषय आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

79. इस निवेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी की गणना अन्य देशों से आयातों पर विचार करने के बाद की जानी चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि बाजार हिस्सेदारी की गणना अन्य देशों से आयात सहित बाजार में उपलब्ध कुल उत्पाद के आधार पर की गई है।

सूची

80. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की सूची स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
प्रारंभिक सूची	एमटी	***	***	***	***
समापन सूची	एमटी	***	***	***	***
औसत सूची	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	89	247	737

81. प्राधिकरण नोट करता है कि चोट की अवधि में घरेलू उद्योग की सूची में काफी वृद्धि हुई है। जबकि भारत में पर्याप्त मांग है, घरेलू उद्योग को इन्वेंट्री के संचय के कारण नुकसान हुआ है।

लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

82. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में की गई है।

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	108	98	117
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	69	64	66
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	-30	-22	-63
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	-30	-17	-28
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	-25	-14	-23
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	-50	-41	-68

### 83. प्राधिकारी नोट करता है:

- क. घरेलू उद्योग ने 2021-22 तक पर्याप्त मुनाफा कमाया। हालांकि, 2022-23 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई। घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हुआ क्योंकि उसने अपनी बाजार हिस्सेदारी को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें कम कर दीं।
- ख. जांच की अवधि के दौरान, आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई।
- ग. घरेलू उद्योग को भी इस अवधि में नकद मुनाफे में गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- घ. घरेलू उद्योग को नियोजित पूंजी पर अपनी वापसी में उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ा है। जबकि घरेलू उद्योग ने 2021-22 तक स्वस्थ रिटर्न अर्जित किया, 2022-23 में निवेश पर इसकी वापसी में गिरावट आई और जांच की अवधि में नकारात्मक था।
- ड. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के संबंध में कि पिछली जांच में नुकसान को वर्तमान जांच में लाभ में बदल दिया गया है, यह ध्यान दिया जाता है कि पिछली जांच के पीओआई (अक्टूबर, 2021 से सितंबर, 2022) के दौरान, एक महत्वपूर्ण घटक, प्रोपलीन ऑक्साइड, जिसका उपयोग पीयूसी के निर्माण के लिए किया गया था, को संबंधित पक्ष से घरेलू स्तर पर (हाथ की लंबाई की कीमत पर) खरीदा गया था और कैप्टिव रूप से भी उत्पादित किया गया था। पिछली चोट अवधि के दौरान हस्तांतरण मूल्य की पद्धति घरेलू खरीद (अर्थात्, संबंधित पक्ष से हाथ की लंबाई की कीमत पर) पर आधारित थी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की कीमत अधिक हो गई, जिससे बिक्री की लागत अधिक हो गई और पीयूसी के लिए परिणामी नुकसान हुआ। समान तुलना के लिए चोट की अवधि के सभी चार वर्षों के लिए एक ही अभ्यास का पालन किया गया था। तथापि, चूंकि आदान कच्चे माल पर बाजार मूल्य पर विचार किया जाता था, इसलिए नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का निर्धारण करने के लिए ऐसे कैप्टिव आदान के लिए नियोजित कोई पूंजी प्रदान नहीं की गई थी। वर्तमान जांच

अवधि में, पीओआई (अक्टूबर, 2023 से सितंबर, 2024) के दौरान, घरेलू उद्योग ने प्रोपलीन ऑक्साइड का निर्माण कैप्टिव रूप से किया और इसे लागत पर स्थानांतरित किया गया। इसलिए, पूरी वर्तमान चोट जांच अवधि के लिए, (जिसमें पिछली जांच अवधि के साथ सामान्य वित्त वर्ष 2020-21 भी शामिल है), समान तुलना के लिए भी उसी अभ्यास का पालन करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, पीयूसी के उत्पादन की लागत का पता लगाने के लिए कैप्टिव इनपुट नामत प्रोपलीन ऑक्साइड के लिए अंतरण मूल्य पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के कैप्टिव इनपुट के लिए नियोजित पूंजी को नियोजित पूंजी में जोड़ा गया है ताकि नियोजित पूंजी पर रिटर्न की अनुमति मिल सके।

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

84. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है:

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	100	100	100
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	99	85	59
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	100	100	100
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	104	42	88

85. प्राधिकारी नोट करता है कि कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता क्षति अवधि में समान रही। तथापि, प्रतिदिन उत्पादकता और कर्मचारियों को दी गई मजदूरी में क्षति अवधि में गिरावट आई।

वृद्धि

विशेष विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	-	-	-
उत्पादन	%	-	-1%	-14%	-31%
घरेलू बिक्री	%	-	-1%	-19%	-46%
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	%	-	-130%	-29%	193%
नकद लाभ	%	-	-125%	-45%	65%

नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-150%	-19%	67%
---------------------	---	---	-------	------	-----

### 86. प्राधिकारी नोट करता है:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ।

ख. घरेलू बिक्री में नकारात्मक वृद्धि हुई।

ग. लाभप्रदता मापदंडों ने महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि दिखाई है क्योंकि घरेलू उद्योग को घाटे का सामना करना पड़ा है और नकारात्मक रिटर्न अर्जित किया है।

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

87. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के संबंध में अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया है। विषय आयात ने घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम माल बेचने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा, विषय आयात ने घरेलू कीमतों को काफी कम कर दिया है, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर रिटर्न में गिरावट आई है। इस प्रकार, विषय आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

डंपिंग का परिमाण

88. प्राधिकारी नोट करता है कि विषय वस्तु को विषय देश से भारत में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

### झ. क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

89. वर्तमान जांच सऊदी अरब से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्कों की अंतिम समीक्षा है। नियमों के तहत, प्राधिकरण को यह निर्धारित करना होता है कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त करने से डंपिंग जारी रहने या फिर से होने की संभावना है और घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है। प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सभी संगत सूचनाओं की जांच की है और नीचे उल्लेख किया है।

#### 1. पाटनरोधी शुल्क के अस्तित्व के बावजूद जारी पाटन

90. यह ध्यान दिया जाता है कि पिछली जांच में विषय देश का डंपिंग मार्जिन 20-30% था, जो अब बढ़कर 90-100% हो गया है। संबंधित देश में निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद देश में वस्तु वस्तुओं का डंप करना जारी रखा है। निरंतर डंपिंग से पता चलता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग के निरंतर और गंभीर होने की संभावना है क्योंकि डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण बना हुआ है।

#### 2. शुल्कों के बावजूद विषय वस्तु के आयातों में वृद्धि

91. यह ध्यान दिया जाता है कि पिछली जांच में विषय देश का डंपिंग मार्जिन 20-30% था, जो अब बढ़कर 90-100% हो गया है। संबंधित देश में निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद देश में वस्तु वस्तुओं का डंप करना जारी रखा है। निरंतर डंपिंग से पता चलता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग के निरंतर और गंभीर होने की संभावना है क्योंकि डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण बना हुआ है।

#### 3. तृतीय देशों को निर्यात की तुलना में भारत को निर्यात

92. प्राधिकारी ने सदारा केमिकल कंपनी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में प्रस्तुत डेटा की जांच की। यह नोट किया गया है कि भारत को निर्यात की मात्रा विषय देश से निर्यातक द्वारा अन्य तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा की तुलना में अधिक दर से बड़ी है।

#### 4. घरेलू उद्योग की कीमतों पर संभावित दमन और उदासीनता प्रभाव

93. रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़ों से पता चलता है कि इंसानरी अवधि के दौरान आयात की कीमतों में लगातार गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कमी आई है। नतीजतन, घरेलू उद्योग को आयात की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा

करने के लिए अपनी कीमतों को अपनी लागत से कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, विषय आयातों ने पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और कम कर दिया है। इसलिए, यदि शुल्कों की अवधि समाप्त होने दी जाती है, तो निर्यातकों को इसकी कीमतों में और गिरावट लाने और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

### 5. घरेलू उद्योग कमजोर स्थिति में है

94. शुल्क लगाए जाने के बावजूद आयातों से घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। सस्ते आयातों की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता मानदंडों में गिरावट आई है। यह एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने के बावजूद है। इस प्रकार, यदि शुल्कों की अवधि समाप्त होने की अनुमति दी जाती है, तो विषय आयात का घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

### 6. जांच अवधि के बाद विषय आयातों की मात्रा और कीमत का रूझान

95. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर दी है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति खराब हो गई है। संबंधित देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि जारी रही है और विषय आयातों की कीमतों में गिरावट जारी रही है। इसका तात्पर्य यह है कि शुल्कों की समाप्ति के मामले में निर्यातक को अपनी वस्तु को भारत में डंप करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

### 7. भारत एक आकर्षक बाजार है

96. प्राधिकारी नोट करता है कि भारत पाटित आयातों के लिए एक आकर्षक बाजार बना हुआ है। जैसा कि उपर्युक्त नोट किया गया है, विषय वस्तु की मांग बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी क्योंकि विषय वस्तु एक वस्तु उत्पाद है और अत्यधिक कीमत-संवेदनशील है। शुल्कों की समाप्ति निर्यातकों को भारत में अपना सामान पाटित करने के लिए और प्रेरित करेगी।

#### ज. गैर-आरोपण विश्लेषण और कार्य-कारण संबंध

##### गैर-आरोपण विश्लेषण

97. क्षति के अस्तित्व, पाटित आयातों के मात्रा और मूल्य प्रभावों की जांच के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति को नियमावली के तहत सूचीबद्ध पाटित आयातों से अन्य किसी कारक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

##### क. तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

98. यह नोट किया गया है कि विषय वस्तु अन्य देशों जैसे चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, कोरिया, ताइवान से महत्वपूर्ण मात्रा में आयात की जा रही है। प्राधिकारी नोट करता है कि चीन और थाईलैंड से आयातों के विरुद्ध एक समानांतर पाटनरोधी जांच आयोजित की जा रही है। इसके अलावा, अन्य देशों से आयात विषय देश की कीमतों से अधिक कीमत पर हैं।

99. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है न कि विषय वस्तु ने। प्राधिकारी नोट करता है कि चीन और थाईलैंड से आयात पहले से ही एक समानांतर पाटनरोधी जांच के अधीन हैं।

##### ख. मांग में संकुचन

100. विषय वस्तु की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और जांच अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। घरेलू उद्योग ने मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं उठाई है।

##### ग. खपत का प्रतिरूप

101. विचाराधीन उत्पाद की खपत के प्रतिरूप में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बन सकता था।

##### घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार-प्रतिबंधी प्रथाएं

102. प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसी कोई व्यापार-प्रतिबंधी प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बन सकती थीं।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

103. विषय वस्तु के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग क्षतिग्रस्त हुआ हो।

च. उत्पादकता

104. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता अधिकांशतः स्थिर रही है। अतः, घरेलू उद्योग ने इस खाते पर क्षति नहीं उठाई है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

105. ऊपर की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। अतः, क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

106. कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि निर्यात बाजार में उद्योग को कीमतें मिलने के बावजूद घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में भी गिरावट आई है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा बेची जाने वाली समान वस्तुओं पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव की जांच तक सीमित है, और क्या वर्तमान शुल्कों की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन जारी रहेगा और चोट पहुंचेगी। इस प्रकार, अपने निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन वर्तमान जांच में महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात की मात्रा इसकी उत्पादन मात्रा की तुलना में काफी कम है।

ज. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

107. क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में जानकारी अलग करके प्रदान की है।

झ. घरेलू उद्योग के संयंत्र पिछड़े एकीकृत नहीं हैं और पुरानी तकनीक का उपयोग

108. इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पिछड़े एकीकरण की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग और मूल्यहास बोझ जैसी अपनी अकुशलताओं के कारण क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसे कारक उद्योग के लिए अंतर्निहित हैं और अपरिवर्तित रहे हैं। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कारकों ने अब घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया है।

ञ. माइचौंग चक्रवात का प्रभाव

109. कुछ इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस क्षेत्र में मिचौंग चक्रवात के कारण हुए शटडाउन के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा होगा। यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग ने चक्रवात के कारण होने वाले शटडाउन के प्रभाव को अलग कर दिया है, और इस तरह के शटडाउन के प्रभाव को दूर करने के लिए अपनी उपलब्ध क्षमताओं को कम कर दिया है। हालांकि, चक्रवात से संबंधित शटडाउन के प्रभाव को ऑफसेट करने की क्षमता में समायोजन करने के बावजूद, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण कम उपयोग का सामना करना पड़ा है और इसके उत्पादन में गिरावट जारी रही है क्योंकि इसकी बिक्री में भी लगातार गिरावट आई है।

कार्य-कारण संबंध स्थापित करने वाले कारक

110. जबकि नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, प्राधिकारी नोट करता है कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

- i. शुल्क लागू होने के बावजूद विषय देश से विषय वस्तु का महत्वपूर्ण पाटन है।
- ii. क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- iii. भारतीय खपत और उत्पादन के संबंध में भी आयात की मात्रा बढ़ी है।
- iv. पाटित आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को बाजार में पारिश्मिक कीमतों पर अपना सामान बेचने से रोका और विषय आयातों ने घरेलू कीमतों को कम करना जारी रखा।

- v. इस अवधि के दौरान लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर अपना सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- vi. ऐसी कम कीमत के आयातों ने मूल्य वृद्धि को रोका जो अन्यथा होती और घरेलू उद्योग की कीमतों को उदास किया।
- vii. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी जबकि आयातों की हिस्सेदारी इस अवधि में बढ़ी।
- viii. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मात्रा क्षति अवधि के दौरान घटी है।
- ix. घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण सूची संचयन का सामना करना पड़ा क्योंकि वह बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ था।
- x. घरेलू उद्योग को घाटा और नकद घाटा हुआ।
- xi. घरेलू उद्योग किए गए निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने में सक्षम नहीं है।

#### ट. क्षति मार्जिन की परिमाण

111. प्राधिकारी ने यथासंशोधित नियमावली की अनुसूची III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विषय वस्तु की क्षतिरहित कीमत जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/डेटा को अपनाकर निर्धारित की गई है।

112. चोट मार्जिन की गणना करने के लिए विषय देशों से लैंडेड मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, चोट की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22%) को नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा है।

113. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रकटीकरण विवरण के अनुसरण में, और उनकी टिप्पणियों पर, प्राधिकारी ने निर्धारणों की पुनः जांच की, और कुछ त्रुटियाँ खोजी गईं, और इन्हें सुधारा गया है, और वही नीचे तालिका में प्रदान किया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी (अमरीकी डॉलर/एमटी)	उतरी हुई कीमत (अमरीकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (अमरीकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (श्रेणी %)
1	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
2	कोई भी अन्य	***	***	***	***	30-40

#### ठ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

##### 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

114. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क शुल्क लगाना जनहित में नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जिससे उपयोगकर्ता आयात पर निर्भर हो जाते हैं।

- ख. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होगी, आपूर्ति अनिश्चितता पैदा होगी, दीर्घकालिक अनुबंधों और निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा, और उन्नत सामग्रियों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विशेष विवरण	इकाई	गणना-1	गणना-2	गणना-3	गणना-4	गणना-5
विशेष विवरण पॉलिओल सीआईएफ कीमत \$1300						
यदि ADD प्रति टन (\$/MT)	\$/MT	50	100	150	200	250
ADD सहित कीमत (\$/MT)	\$/MT	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550
ADD सहित कीमत (₹/MT)	₹/MT	1,12,725	1,16,900	1,21,075	1,25,250	1,29,425
ADD सहित पहुँच कीमत (₹/MT)	₹/MT	1,21,225	1,25,400	1,29,575	1,33,750	1,37,925
फोम लागत में पॉलिओल का योगदान (₹/MT)	₹/MT	78,796	81,510	84,224	86,938	89,651
उपज हानि के लिए समायोजित शुद्ध योगदान (₹/MT)	₹/MT	98,495	1,01,888	1,05,280	1,08,672	1,12,064
गद्दे प्रति फोम (Kg)	Kg	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
लागत योगदान (₹)	₹	1,202	1,243	1,284	1,326	1,367
गद्दे प्रति पॉलिओल ADD की लागत (₹)	₹	41	83	124	165	207
खुदरा बिक्री पर प्रभाव (₹)	₹	124	248	372	496	620

विशेष विवरण	Unit					
पॉलिओल	\$/MT	300	350	400	450	500
सीआईएफ कीमत \$1300	\$/MT	1,600	1650	1,700	1,750	1,800
यदि ADD प्रति टन (\$/MT)	Rs/MT	1,33,600	1,37,775	1,41,950	1,46,125	1,50,300
ADD सहित कीमत (\$/MT)	Rs/MT	1,42,100	1,46,275	1,03,220	1,54,625	1,58,800
ADD सहित कीमत (₹/MT)	Rs/MT	92,365	95,079	97,793	1,00,506	1,03,220
ADD सहित पहुँच कीमत (₹/MT)	Rs/MT	1,15,456	1,18,848	1,22,241	1,25,633	1,29,025
फोम लागत में पॉलिओल का योगदान (₹/MT)	Kg	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
उपज हानि के लिए समायोजित शुद्ध योगदान (₹/MT)	Rs	1,408	1,449	1,491	1,532	1,573
गद्दे प्रति फोम (Kg)	Rs	248	290	331	372	414
लागत योगदान (₹)	Rs	745	869	993	1,117	1,241

- ग. एफएसपी और टीडीआई जैसे प्रमुख कच्चे माल पर शुल्क लगाने के बाद एफएसपी पर शुल्क लगाना डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर भारी बोझ डालेगा जिसे एमएसएमई उपयोगकर्ता नहीं उठा सकते।
- घ. आवेदक ने 20,000 रुपये के गद्दे पर विचार करके प्रस्तावित कर्तव्यों के प्रभाव को कम करके आंका है, जो मुख्यधारा के भारतीय गद्दे खंड की कीमत की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- ङ. अधिकांश गद्दे, विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा उत्पादित गद्दे, 6,000 से 8,000 मूल्य सीमा के भीतर आते हैं और इस सेगमेंट के लिए, एफएसपी की लागत में मामूली वृद्धि के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होगी।
- च. डाउनस्ट्रीम उद्योग में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्माता शामिल हैं। शीला फोम ने दावा किया कि 20-25 बड़े निर्माता हैं, लेकिन इस तरह के उद्यमों की प्रकृति के बारे में कोई संदर्भ नहीं है।
- छ. इनपुट लागत में अचानक वृद्धि के लिए एमएसएमई की संवेदनशीलता को एमएसएमईडी अधिनियम के माध्यम से पहचाना जाता है।
- ज. आवेदक यह मांग नहीं कर सकता है कि एमएसएमई अपने प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करने से पहले वास्तविक बंद होने का प्रदर्शन करें।
- झ. जबकि याचिकाकर्ता अपने स्वयं के संचालन के लिए सुरक्षा को उचित ठहराने के लिए "मेक इन इंडिया" नीति पर भरोसा करता है, साथ ही जब एमएसएमई-प्रभुत्व वाले डाउनस्ट्रीम क्षेत्र की बात आती है तो वह

इसकी अवहेलना करता है।

- ज. मांग-आपत के अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास देश में मौजूदा मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है।
- ट. डंपिंग रोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है क्योंकि इससे उपयोगकर्ता उद्योग की उत्पादन लागत में तेजी से वृद्धि होगी, पहले से ही कम मार्जिन में कमी आएगी और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जोखिम हानि, उत्पादन में कटौती या शटडाउन होगा।
- ठ. डाउनस्ट्रीम निर्माताओं को पहले से ही प्रमुख इनपुट पर शुल्क से उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे एफएसपी पर अतिरिक्त शुल्क टिकाऊ नहीं होता है।

## 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

115. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

क. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं की लागत पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। 20,000 रुपये की कीमत वाले गद्दे के लिए, वर्तमान शुल्कों की सीमा तक शुल्क लगाने से केवल 0.63% का प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, 6,000 रुपये के गद्दे के संबंध में, प्रभाव केवल 0.71% होगा।

विवरण	इकाई	A	B
एक गद्दे (Mattress) की कीमत	₹/इकाई	20,000	6,000
वजन	किग्रा/इकाई	30	10
एक गद्दे में प्रयुक्त FSP	किग्रा/इकाई	6	2
FSP का वर्तमान मूल्य	₹/किग्रा	98	98
एक गद्दे में FSP की लागत	₹	589	196
FSP पर वर्तमान शुल्क	\$/MT	253	253
FSP पर वर्तमान शुल्क	₹/किग्रा	21	21
प्रस्तावित एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) का प्रभाव	₹/किग्रा	126	42
प्रस्तावित ADD का प्रभाव	%	0.63%	0.71%

- ख. फोम के लिए प्रमुख कच्चे माल एफएसपी और टीडीआई पर प्रस्तावित शुल्कों का कुल प्रभाव केवल 2.4% होगा। 6,000 रुपये के गद्दे के लिए, प्रस्तावित शुल्कों का कुल प्रभाव केवल 144 रुपये प्रति गद्दा होगा।
- ग. उपयोगकर्ताओं की ओर से गणना किए गए कर्तव्यों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह गलत सीआईएफ मूल्य, लागू सीमा शुल्क और उपभोग कारक पर निर्भर करता है। इसके अलावा, प्रभाव की गणना उपयोगकर्ताओं के मार्जिन पर की गई है, न कि ऐसे उपयोगकर्ताओं की लागत पर।
- घ. फोम उद्योग एक पासथ्रू उद्योग है और शुल्क लगाने का प्रभाव हमेशा गद्दा उद्योग पर पड़ेगा।
- ड. शुल्क लगाना प्रयोक्ताओं के लिए नुकसानदेह नहीं होगा क्योंकि शुल्क लगाने के बाद भी आयात मूल्य संबंधित देशों के घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य से कम होगा।
- च. अन्य देशों से आयात पर शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं की लाभप्रदता प्रभावित नहीं हुई है।

- छ. जबकि उपयोगकर्ता खुद को एमएसएमई होने का दावा कर रहे हैं, कुछ उपयोगकर्ताओं ने बंपर मुनाफा कमाया है, जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व के दोगुने से भी अधिक है।
- ज अपने दावों के विपरीत, उपयोगकर्ता संघ ने अपने सदस्यों, एमएसएमई क्षेत्र में शामिल सदस्यों की संख्या या कुल खपत में ऐसे एमएसएमई उत्पादकों की खपत हिस्सेदारी के बारे में विवरण प्रदान नहीं किया है।
- झ कीमतों में वृद्धि से उत्पाद की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 2021-22 में कीमतें अधिक होने पर भी एफएसपी की मांग महत्वपूर्ण बनी हुई थी।
- ञ घरेलू उद्योग वर्तमान में अपनी क्षमता का विस्तार करने की प्रक्रिया में है, जो वर्तमान में खतरे में है। देश में विषय वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक की रक्षा करने की आवश्यकता है।
- ट. इस दावे के विपरीत कि मांग-आपत के अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है, डंप किए गए आयात किसी भी मांग-आपत अंतर से अधिक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
- ठ यह एक सुस्थापित सिद्धांत रहा है कि जहां मांग-आपत का अंतर होता है वहां आयात अपरिहार्य होता है, लेकिन यह पाटन का औचित्य नहीं हो सकता है।
- ड जबकि घरेलू उद्योग उचित बाजार स्थितियों को पुनः स्थापित करने की मांग कर रहा है, प्रयोक्ता अनुचित मूल्यों पर आयात की उपलब्धता की मांग कर रहे हैं। यदि उपयोगकर्ताओं का संचालन उचित कीमतों पर आयात के आधार पर जीवित नहीं रह सकता है, तो यह उनके संचालन की अक्षमता को रेखांकित करता है।
- ढ. उत्पाद को जापान, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे अन्य देशों से और संबंधित देशों से उचित मूल्य पर आयात किया जा सकता है।
- ण प्रोपलीन ऑक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से आवेदक द्वारा एफएसपी के उत्पादन में किया जाता है और शुल्क न लगाने से प्रोपलीन ऑक्साइड प्रचालनों की व्यवहार्यता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- त. शुल्क न लगाने से आवेदक को एफएसपी के लिए परिचालन स्थायी रूप से बंद करने और अन्य उत्पादों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- थ शुल्क न लगाने से उपयोगकर्ता विषय आयात पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, जिससे विषय आयात का एकाधिकार पैदा होगा। ऐसी स्थिति में, निर्यातक एकाधिकार की स्थिति का लाभ उठा सकते हैं और लाभ को अधिकतम करने के लिए उपयोगकर्ताओं का शोषण कर सकते हैं।

### 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

116. प्राधिकरण का कहना है कि डंपिंग रोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य डंपिंग की अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार हो सके। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य संबंधित देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह एक समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकरण स्वीकार करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क की दृढ़ता भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर को प्रभावित कर सकती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को लागू करने से अछूता रहेगा। प्रतिस्पर्धा में कमी के बजाय, डंपिंग रोधी उपायों को लागू करने से डंपिंग प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ को रोकने का काम किया जाता है। यह विषय वस्तुओं के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, एंटी-डंपिंग शुल्क एक बाधा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष-व्यापार प्रथाओं का एक सूत्रधार है।

117. प्राधिकरण ने शुरुआत अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी इच्छुक पार्टियों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आथक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

118. घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है बल्कि केवल उचित मूल्य सुनिश्चित होता है। अन्यथा भी, विषय वस्तुओं का उत्पादन कई गैर-विषय देशों में भी किया जाता है, जैसे कि

सिंगापुर यूएसए, जापान, कोरिया। इसलिए, उपयोगकर्ता घरेलू उद्योग और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

119. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने 20,000 रुपये के गद्दे पर विचार करके प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव को कम करके आंका है, जबकि अधिकांश गद्दे 6,000 से 8,000 रुपये के भीतर आते हैं। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि शुल्क लगाने से 20,000 रुपये की कीमत वाले गद्दे के लिए 0.6% और 6,000 रुपये की कीमत वाले गद्दे के लिए 0.71% का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, किसी भी मामले में, गद्दे की कीमतों पर कर्तव्यों का प्रभाव नगण्य होगा।

120. प्राधिकरण ने सभी पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को नोट कर लिया है। एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद का 12.2 किलोग्राम गद्दे के प्रति टुकड़े की खपत होती है। 1300 अमेरिकी डॉलर के आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, इसका तात्पर्य यह है कि विचाराधीन उत्पाद 6000 रुपये में बेचे जाने वाले गद्दे की कीमत का लगभग 20% है (और 8000 में बेचे गए गद्दे के लिए 15%)। इसलिए, प्राधिकरण ने पाया कि यदि विचाराधीन उत्पाद के कारण लागत गद्दे के लिए केवल 15-20% है, तो कीमत में 10%, 20% या 30% की वृद्धि केवल 1.5% -6% के क्षेत्र में होगी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने नोट किया है कि वर्तमान जांच एक सनसेट समीक्षा जांच है और इच्छुक पक्षकारों ने वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के मूल्य में वृद्धि दर्शाने वाले साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। नीचे दी गई तालिका 6000 रुपये में बेचे जाने वाले गद्दे की कीमत में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है।

विशेष विवरण	इकाई	टिप्पणी	मूल्य
पॉलिओल की सीआईएफ कीमत	अमेरिकी डॉलर/एमटी	A	1,300
फोम में पॉलिओल का शुद्ध योगदान	₹/किग्रा	B	95
प्रति गद्दा फोम	किग्रा	C	12.2
गद्दे में पॉलिओल की लागत	₹/किग्रा	D = C*B	1,160
गद्दे की कीमत	₹	E	6,000
गद्दे में पॉलिओल की हिस्सेदारी	%	F = D/E	19%
गद्दे की कीमत पर 10% ADD का प्रभाव	%	F*10%	1.9%
गद्दे की कीमत पर 20% ADD का प्रभाव	%	F*20%	3.8%
गद्दे की कीमत पर 30% ADD का प्रभाव	%	F*30%	5.7%

121. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

122. कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात अपरिहार्य है और उन्हें आयात के लिए उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्राधिकरण का कहना है कि मांग-आपूर्ति का अंतर भारत में डंपिंग का औचित्य नहीं है। यहां तक कि अगर देश में मांग-आपूर्ति का अंतर है, तो यह आवश्यक है कि उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि यह उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। वास्तव में, बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थापना से आगे निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो मांग-आपूर्ति के अंतर को और पाटने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट, गुजरात सरकार से घरेलू उद्योग को गुजरात में

उत्पादन सुविधा स्थापित करने की अनुमति देने और विस्तार का जिक्र करते हुए निवेशक प्रस्तुतियों के रूप में साक्ष्य प्रदान किए हैं और प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग वर्तमान में गुजरात राज्य में अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की प्रक्रिया में है। और इन क्षमताओं के ऑनलाइन होने के बाद बाजार हिस्सेदारी के एक बड़े हिस्से को पूरा करने में सक्षम होगा।

123. सार्वजनिक हित में उपभोक्ता हित और उत्पादक हित दोनों शामिल हैं, जो दोनों महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपभोक्ता हित अत्यधिक प्रासंगिक हैं, खासकर माल की अंतिम खपत के मामले में। हालांकि, उत्पादक हित समान रूप से प्रासंगिक हैं, यदि अधिक नहीं। COVID-19 महामारी जैसे जीवन में एक बार आने वाले संकटों के दौरान निर्माता हित विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए। इसलिए, यह आवश्यक है कि उपभोक्ता हितों के साथ-साथ उत्पादक हितों को भी उचित महत्व दिया जाए, यदि अधिक महत्व नहीं दिया जाए।

124. प्राधिकरण ने आगे कहा कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने महत्वपूर्ण विस्तार किया है जिसे डंपिंग के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है। शुल्क न लगाने से घरेलू उद्योग को एफएसपी के लिए अपने परिचालन को स्थायी रूप से बंद करने और अन्य उत्पादों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए, घरेलू उद्योग के संचालन और किए गए निवेशों की व्यवहार्यता की रक्षा के लिए कर्तव्यों को लागू करना आवश्यक है।

125. घरेलू उद्योग ने यह भी जोर दिया है कि प्रोपलीन ऑक्साइड मुख्य रूप से विषय वस्तु के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसलिए, शुल्क न लगाने से प्रोपलीन ऑक्साइड उद्योग के संचालन की व्यवहार्यता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

#### ड. प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियां

126. प्राधिकारी ने 5 मार्च 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटीकरण विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जांच प्रासंगिक समझे जाने की सीमा तक की है। शुल्कों के पिछले इतिहास, पिछड़े एकीकरण की कमी, चक्रवात का प्रभाव, अन्य आयातों का प्रभाव और देश में मांग-आपूर्ति अंतर के अस्तित्व के संबंध में प्रस्तुतियां पिछली प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं और संक्षिप्तता के लिए नहीं दोहराई गई हैं।

#### 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

127. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित नई प्रस्तुतियां की हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद गुणवत्ता और तकनीकी विशेषताओं के मामले में नीच है। इसमें उच्च पोटेथियम अवशेष होते हैं, जो कोई मामूली भिन्नता नहीं है और सीधे डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए प्रक्रियात्मकता को प्रभावित करता है, जो बड़े पैमाने पर एमएसएमई हैं।
- ख. प्राधिकरण ने इस तथ्य की अवहेलना की है कि केओएच प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित उत्पाद में पोटेथियम अवशेष काफी अधिक है जो उत्पाद को पॉलिमर पॉलीओल में खपत के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी बना देता है। समायोजित प्रक्रिया शर्तों के तहत कुछ ग्राहकों द्वारा सीमित उपयोग एक ही उत्पाद के दायरे में तकनीकी रूप से विशिष्ट उत्पादों को शामिल करने को उचित नहीं ठहरा सकता है।
- ग. पिछली जांच और इस जांच में 2021-22 के लिए प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट की गई आयात मात्रा में महत्वपूर्ण अंतर हैं।
- घ. प्रकटीकरण विवरण में मांग, बाजार हिस्सेदारी, मूल्य में कमी और चोट जैसे प्रमुख निष्कर्षों के आधार का उचित रूप से खुलासा नहीं किया गया है।
- ड. प्राधिकरण इस तथ्य को संबोधित करने में विफल रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत तकनीकी डेटा शीट विस्कोलेस्टिक पॉलीथर पॉलीओल से संबंधित है, न कि एफएसपी से, जो स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- च. प्राधिकरण फोम निर्माताओं पर शुल्क लगाने के प्रभाव की गणना करने में विफल रहा है और केवल खुदरा-मूल्य अभ्यास के एक साधारण प्रतिशत के रूप में गद्दे पर प्रभाव की गणना की है। इसके अलावा, टीडीआई पर मौजूदा कर्तव्यों के आलोक में कर्तव्यों के प्रभाव को देखा जाना चाहिए।
- छ. डाउनस्ट्रीम उद्योग सीमित मार्जिन पर काम करता है और एक प्रमुख कच्चे माल की लागत में थोड़ी सी भी वृद्धि मार्जिन को प्रभावित कर सकती है और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकती है।

- ज. केवल इसलिए कि आवेदक क्षमताओं का विस्तार कर रहा है जो भविष्य में चालू हो सकता है, उपयोगकर्ताओं को वर्तमान लागत वृद्धि को वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
- झ. मध्य-पूर्व क्षेत्र में चल रहे भू-राजनीतिक व्यवधान को ध्यान में रखते हुए, सऊदी अरब से आयात पहले से ही बाधित है और शुल्क लगाने से बोझ बढ़ जाएगा।
- ञ. शुल्क वर्तमान मामले के चोट मार्जिन पर आधारित होना चाहिए और अतीत में निर्धारित शुल्क को जारी नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की लागत के निर्धारण के लिए लागत पद्धति बदल गई है।
- ट. सडारा केमिकल्स के लिए सामान्य मूल्य अत्यधिक बढ़ाया जाता है और इसे संशोधित किया जाना चाहिए।
- ठ. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की भागीदारी को विधिवत मान्यता दी जानी चाहिए।
- ड. सदर के लिए निर्धारित बिक्री चैनल गलत है और इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

## 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

128. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित नई प्रस्तुतियां की हैं:

- क. रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि आवेदक ने महत्वपूर्ण निवेश किया है और अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध है, जो मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने में मदद करेगा।
- ख. कर्तव्यों को जारी रखने से आवेदक को अपने संचालन को स्थायी रूप से बंद करने और मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए किए गए महत्वपूर्ण निवेश से बचाया जा सकेगा।
- ग. गद्दे की सबसे कम कीमत के आधार पर गणना किए गए कर्तव्यों का संभावित प्रभाव सटीक नहीं है क्योंकि बाजार में विभिन्न कीमतों पर गद्दे पेश किए जाते हैं। गद्दे की विभिन्न कीमतों पर विचार करने पर शुल्क का प्रभाव भी नगण्य होगा।
- घ. कुल कच्चे माल की लागत की गणना खरीदे गए कच्चे माल की लागत की अवहेलना करते हुए की गई है, जो खपत किए गए कुल कच्चे माल में महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- ड. उपयोगिता लागत को केवल 1 संयंत्र में खपत की गई उपयोगिता की लागत पर विचार करके गलत तरीके से निर्धारित किया गया है, जबकि दूसरे संयंत्र के लिए खपत कारक को लागू किया गया है। उपयोगिता लागत को उस संयंत्र के लिए खपत कारक पर विचार करके संशोधित किया जाना चाहिए जिसकी लागत पर विचार किया गया है।

## 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

129. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियों की जांच की है और नोट किया है कि कुछ टिप्पणियां प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार इच्छुक पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे जाने वाले मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

130. कुछ इच्छुक पक्षकारों ने डीएमसी उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित एफएसपी को बाहर रखने के अपने अनुरोध को दोहराया है। पार्टियों ने यह दावा करते हुए अपनी दलीलें दोहराई हैं कि केओएच उत्प्रेरक मार्ग का उपयोग करके घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद गुणवत्ता में हीन है और इसका उच्च पोटेथियम अवशेष उत्पाद को डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी बनाता है। यह दावा किया गया है कि संबंधित देशों में निर्यातक डीएमसी उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं और इस प्रकार, बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद की आपूर्ति के अभाव में उपयोगकर्ताओं को आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

131. प्राधिकरण ने दोनों पक्षों द्वारा प्रदान की गई प्रस्तुतियों और सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की है। यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग (KOH उत्प्रेरक उत्पाद) द्वारा उत्पादित उत्पाद में अंतर और अन्य देशों से आयातित (DMC उत्प्रेरक उत्पाद) के बारे में तर्क पिछली जांच में भी प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए थे। हालाँकि, प्राधिकरण को पता चलता है कि वर्तमान जांच में मांगे गए बहिष्करण का समर्थन करने या पिछली जांच में प्राप्त निष्कर्षों से प्रस्थान की गारंटी देने के लिए कोई अतिरिक्त औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

132. इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने बाजार में उपयोगकर्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करना जारी रखा है, जो विषय वस्तुओं का आयात भी कर रहे हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपयोगकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों को खरीद और उपयोग कर रहे हैं और जो विषय देशों से एक दूसरे के स्थान पर आयात किए जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, डीएमसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद को बाहर रखना आवश्यक नहीं है।

133. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कच्चे माल और उपयोगिता लागत के खाते पर क्षतिरहित कीमत को संशोधित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पीयूसी के लिए कच्चे माल की दरें (कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल सहित) पाटनरोधी शुल्क नियमों की अनुसूची III में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन क्षमता और अनुकूलन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति अवधि में उपयोगिता के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, टीम द्वारा की गई सत्यापन और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के आधार पर आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

134. इस तर्क के संबंध में कि केवल गद्दे के संबंध में कर्तव्यों के प्रभाव की गणना नहीं की जानी चाहिए, यह ध्यान दिया जाता है कि इच्छुक पक्षों में से किसी ने भी रिकॉर्ड पर जानकारी प्रस्तुत नहीं की है जो प्राधिकरण को किसी अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर कर्तव्यों के प्रभाव को निर्धारित करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के साथ-साथ उपयोगकर्ता संघ ने भी केवल गद्दे के संबंध में प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। रिकॉर्ड पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, प्राधिकरण को इस तर्क में कोई दम नहीं लगता है।

135. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि शुल्कों के प्रभाव पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि अन्य प्रमुख कच्चे माल, अर्थात् टीडीआई पर भी एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए गए हैं। प्राधिकरण ने पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार किया है। यह नोट किया जाता है कि टीडीआई के आयात पर 344.33 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि एफएसपी और टीडीआई पर शुल्कों का संचयी प्रभाव गद्दे के संबंध में केवल 2.4% की सीमा में होगा।

विशेष विवरण	इकाई	टिप्पणी	मूल्य
पॉलिओल की सीआईएफ कीमत	अमेरिकी डॉलर/एमटी	A	1,300
फोम में पॉलिओल का शुद्ध योगदान	₹/किग्रा	B	95
प्रति गद्दा फोम	किग्रा	C	12
गद्दे में पॉलिओल की लागत	₹/किग्रा	D = C*B	1,160
गद्दे की कीमत	₹	E	6,000
गद्दे में पॉलिओल की हिस्सेदारी	%	F = D/E	19%
गद्दे की कीमत पर 10% का प्रभाव	%	G = F*10%	1.9%

गद्दे की कीमत पर 10% का प्रभाव	₹/किग्रा	$H = G/E$	116
टीडीआई पर शुल्क	₹/किग्रा	$I = (344.33*83.50)/1000$	29
गद्दे की कीमत पर कुल प्रभाव	₹/किग्रा	$J = H+I$	145
गद्दे की कीमत पर कुल प्रभाव	%	$K = J/E$	2.4%

136. सदारा केमिकल्स के लिए शुल्कों को संशोधित करने के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सहयोगी उत्पादक और निर्यातक की प्रतिक्रिया की जांच करने के बाद सदारा के सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और उतरी कीमत की गणना की गई है, और ये सभी पैरामीटर प्रकटीकरण विवरण में सदारा के साथ साझा किए गए थे। प्राधिकारी ने सभी गणनाओं की पुनर्जांच की है, और उतरी कीमत के संबंध में सुधार किए गए हैं, और वही इन अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक शीर्षकों में उल्लेखित है।

137. यह भी तर्क दिया गया है कि सदारा केमिकल्स के लिए सामान्य मूल्य को संशोधित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सामान्य मूल्य सदारा द्वारा दाखिल की गई प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए और प्रासंगिक पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

138. सहकारी निर्यातक के बिक्री चैनल के संबंध में, वही इन अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक शीर्षकों में सुधारी गई है।

139. जहां तक इस दलीलों के संबंध में कि प्राधिकरण द्वारा परिमाणित आयात की मात्रा गलत है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा चोट की जांच में उल्लिखित आयात की मात्रा डीजी सिस्टम डेटा के अनुसार देश-वार आयात मात्रा से संबंधित है। वास्तव में, चोट की अवधि में सभी वर्षों के लिए आयात की मात्रा डीजी सिस्टम डेटा से ली गई है।

140. प्रकटीकरण बयान पर टिप्पणियों के बाद, प्राधिकरण ने समय सीमा के भीतर DCIPL (I) लिमिटेड द्वारा आयातकों की प्रश्नावली प्राप्त करने की स्वीकृति स्वीकार की है।

141. निवल निर्यात मूल्य और लैंडेड मूल्य की पुनः गणना के बारे में एसएबीआईसी की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकरण ने सभी गणनाओं की फिर से जांच की है, और यह नोट किया गया है कि जबकि शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना नियमों के अनुसार सही ढंग से की गई है, हालांकि, लैंडेड मूल्य निर्धारण को ठीक कर दिया गया है।

#### ढ. निष्कर्ष

142. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच के बाद; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि:

- विचाराधीन उत्पाद 3000-4000 के आण्विक भार वाला फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल है।
- विचाराधीन उत्पाद में दोनों मार्गों का उपयोग करके उत्पादित अंतिम उत्पाद के तकनीकी और भौतिक गुणों में समानता को देखते हुए केओएच मार्ग और डीएमसी उत्प्रेरक मार्ग का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा, दोनों मार्गों का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद का उपयोग अंतिम अनुप्रयोगों में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।
- घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु उत्पादित किया है।
- पाटनरोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा के लिए आवेदन मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया था।

- v. आवेदक देश में विषय वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है, और घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र माना गया है।
- vi. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए, विषय देश से विषय वस्तु का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से ऊपर और महत्वपूर्ण है।
- vii. विषय वस्तु की मांग पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है।
- viii. घरेलू उद्योग ने प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद विषय वस्तु के कारण क्षति सहना जारी रखा है, जो निम्नलिखित से स्पष्ट है:
- क. क्षति अवधि में निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टि से आयात की मात्रा बढ़ती रही और जांच अवधि में सबसे अधिक थी।
- ख. आयात की मात्रा देश में मांग में वृद्धि की दर से अधिक दर पर बढ़ी।
- ग. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।
- घ. विषय वस्तु की पहुँच कीमत क्षति अवधि के दौरान लगातार घटती रही है।
- ङ. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत इस अवधि में बढ़ी, जबकि आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट के जवाब में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत घटी।
- च. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी।
- छ. मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा।
- ज. घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से कम-उपयोगित क्षमताओं का सामना करना पड़ा।
- झ. घरेलू उद्योग बाजार में अपना उत्पाद निपटाने में असमर्थ था जिसके परिणामस्वरूप सूची जमा हो गई।
- ञ. घरेलू उद्योग ने आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी लागत से कम कीमत पर विषय वस्तु की आपूर्ति की।
- ट. घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण घाटे और नकद घाटे हुए।
- ठ. घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक है।
- ड. आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- ix. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की निरंतरता की संभावना है, जो निम्नलिखित से स्पष्ट है:
- क. विषय देश के निर्यातकों ने शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन करना जारी रखा है।
- ख. निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टि से आयात की मात्रा बढ़ती रही है।
- ग. सहकारी उत्पादक की प्रतिक्रिया से देखते हुए, तृतीय देशों को निर्यात में वृद्धि की तुलना में भारत को निर्यात की मात्रा अधिक दर पर बढ़ी है।
- घ. आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों को दबाने या उदास करने की संभावना है।
- ङ. घरेलू उद्योग ने शुल्कों के बावजूद क्षति सहना जारी रखा है और इस प्रकार, आगे क्षति के प्रति कमजोर है।
- च. पीओआई के बाद की अवधि में आयात की मात्रा बढ़ती रही है, जबकि आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट जारी रही है।
- x. विषय देश के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक है।
- xi. कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बना है।

- xii. पिछड़े एकीकरण की अनुपस्थिति जैसे कारक घरेलू उद्योग के लिए अंतर्निहित हैं और अपरिवर्तित रहे हैं, अतः ये अब घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बन सकते।
- xiii. घरेलू उद्योग ने अपनी उपलब्ध क्षमताओं को कम करके माइचौंग चक्रवात के प्रभाव को अलग किया। तथापि, इसके बावजूद, घरेलू उद्योग को क्षमताओं के महत्वपूर्ण अल्प-उपयोग और उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा।
- xiv. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति उठाई है।
- xv. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जनहित में है और आम जनता के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xvi. शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद की कीमतों में नगण्य वृद्धि होगी।
- xvii. घरेलू उद्योग ने बाजार में अपने उत्पाद की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादन क्षमताओं को विस्तारित करने में महत्वपूर्ण निवेश किया है।
- xviii. शुल्क लगाना घरेलू उद्योग के संचालन और किए गए निवेशों की व्यवहार्यता की रक्षा के लिए आवश्यक है।
- xix. शुल्क न लगाने से प्रोपलीन ऑक्साइड के अपस्ट्रीम उद्योग के संचालन की व्यवहार्यता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

#### ण. सिफारिशें

143. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच प्रारंभ की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को शुल्क समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पाटन और क्षति की निरंतरता है और यदि पाटनरोधी उपायों को समाप्त होने की अनुमति दी गई तो आगे क्षति होने की संभावना है, प्राधिकारी का मत है कि विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उपायों की निरंतरता आवश्यक है। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम फा.सं. 6/20/2019-डीजीटीआर, दिनांक 1 सितंबर 2020 में अधिसूचित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की सिफारिश करना उचित समझता है।

144. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अधिसूचना की तारीख से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, विषय देशों से 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश की जाती है।

#### शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण	उत्पत्ति देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3907291 0, 3907299 0	3000- 4000 के आण्विक भार का फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सदारा केमिकल कंपनी	150.06	एमटी	अमरीकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी	क्र.सं. 1 में उल्लिखित के अलावा	235.02	एमटी	अमरीकी डॉलर

				देश	अन्य कोई			
3.	-वही-	-वही-	सऊदी अरब के अलावा अन्य कोई देश	सऊदी अरब	कोई भी	235.02	एमटी	अमरीकी डॉलर

145. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क प्राधिकरणों को एक वैध वाणिज्यिक चालान की प्रस्तुति के अधीन होगा, जिस पर ऐसे चालान जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणापत्र होगा, जिसे उसके नाम और पदनाम से पहचाना जाएगा, जो निम्नानुसार तैयार किया जाएगा:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में शामिल भारत को निर्यात के लिए बेचे गए फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल की (मात्रा) का निर्माण [संबंधित देश] में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण और सही है।"

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

#### त. आगे की प्रक्रिया

146. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, प्राधिकृत अधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

Directorate General of Trade Remedies, DGTR

NOTIFICATION

(FINAL FINDINGS)

New Delhi, the 17th March, 2026

Case No. AD (SSR)- 01/2025

**Subject: Sunset review investigation of anti-dumping duty concerning imports of "Flexible Slabstock Polyol" originating in or exported from Saudi Arabia.**

**F. No. 07/03/2025-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules);

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. Manali Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules) for initiation of sunset review of the anti-dumping duty concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as “FSP” or the “product under consideration” or the “subject goods”). The applicant had filed the application requesting for initiation of review with respect to anti-dumping duty on imports from Singapore, Saudi Arabia and UAE. However, at the time of initiation, the Authority noted that the application requesting review of duties on imports from Singapore was not filed within the timeline prescribed under Trade Notice No. 2/2017, dated 12<sup>th</sup> December 2017. Further, it was noted that there are no known producers of the product under consideration in UAE which can export the subject goods to India. Thus, the Authority did not initiate the review with respect to duties on imports from Singapore and UAE. Accordingly, the present review is with respect to imports of the product under consideration from Saudi Arabia (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The original investigation concerning imports of subject goods originating in or exported from Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE) was initiated by the Authority vide Notification No. 6/20/2019-DGTR, dated 18<sup>th</sup> September 2019. The Authority notified the Final Findings vide Notification No. 6/20/2019-DGTR, dated 1<sup>st</sup> September 2020 and recommended imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from Saudi Arabia and UAE. Subsequently, the Ministry of Finance imposed anti-dumping duties vide Notification No 20/2021- Customs (ADD), dated 5<sup>th</sup> April 2021.
3. In terms of Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23(1B) of Rules, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. The applicant filed an application dated 29<sup>th</sup> January 2025, seeking initiation of sunset review of anti-dumping duties imposed earlier and continuation of anti-dumping duties on imports of Flexible Slabstock Polyol. The request was based on the grounds that the expiry of duty was likely to result in continuation of dumping of the product under consideration and injury to the domestic industry.
5. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence substantiating likelihood of continuation of dumping and injury, in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority issued a public notice initiating the sunset review of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from Saudi Arabia, vide Notification No. 07/03/2025-DGTR, dated 18<sup>th</sup> March 2025, published in the Gazette of India. The Authority initiated the review of anti-dumping duty imposed earlier to examine whether the expiry of anti-dumping duty on imports of subject goods from Saudi Arabia is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

**6.1 Initiation**

- a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 of the Rules.

- b. The Authority issued a public notice dated 18<sup>th</sup> March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a sunset review of anti-dumping duty concerning imports of subject goods from the subject country.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

### **6.2 Circulation of non-confidential version of the application**

- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

### **6.3 Participation by Exporters of Subject Country**

- e. The Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/exporters from the subject country, known importers/ users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing by the extended timeline.
- f. The Authority sent the Exporters' Questionnaire to the following known producers/ exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - 1. Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
  - 2. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
  - 3. SABIC Asia Pacific Pte. Ltd., (SAPPL), Singapore
  - 4. Dow Chemical International Private Limited (DCIPL) Dubai Branch, UAE
  - 5. Dow Saudi Arabia Marketing B.V., (DSAPM BV, Netherland
  - 6. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore
- g. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- h. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
  - 1. Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
  - 2. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
  - 3. SABIC Asia Pacific Pte. Ltd., (SAPPL), Singapore
  - 4. Dow Chemical International Private Limited (DCIPL) Dubai Branch, UAE
  - 5. Dow Saudi Arabia Marketing B.V., (DSAPM BV, Netherland
  - 6. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore
  - 7. Dow Chemical International Private Limited

### **6.4 Participation by Importers/Users**

- i. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

1. Wanhua International (India) Pvt. Ltd.
  2. Sheela Foam Ltd. (SFL)
  3. Tirupati Foam Ltd.
  4. M.H. Polymers Ltd.
  5. Toyota Tsusho India Pvt. Ltd.
  6. Dow Chemical International Private Limited, India (DCIPL)
- j. In response to the initiation of the subject investigation notification, following importers/users have responded by filing questionnaire response:
1. Sheela Foam Limited (SFL)
  2. Expanded Polymer Systems Private Limited
- k. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Indian Polyurethane Association as well. The Association made submissions during the course of the review.
- l. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Department of Chemical and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. However, the Authority has not received any comments.
- m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- n. An opportunity was provided by the Authority to all interested parties to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology.
- o. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- p. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, as per the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

#### **6.5 Period of Investigation and Injury Period**

- q. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> October 2023 to 30<sup>th</sup> September 2024 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

#### **6.6 Further procedures**

- r. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 3<sup>rd</sup> December 2025. The parties presented their views in the oral hearing and were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- s. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.

- t. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 5<sup>th</sup> March 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority, has not been repeated for the sake of brevity.
- u. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- v. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- w. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present disclosure statement to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary
- x. ‘\*\*\*’ in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 84.27.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

#### C.1. Submissions by other interested parties

- 7. The following submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of the product under consideration and like article.
  - a. Products produced using Double Metal Cyanide (DMC) Catalyst technology and Potassium Hydroxide (KOH)-based catalyst method used by the domestic industry, are not comparable.
  - b. DMC-based FSP is preferred in high-performance applications because it delivers narrower molecular weight distribution, enhancing consistency, reduces creation of by-products, improves product purity, enables higher primary hydroxyl content and better reactivity.
  - c. The product produced using KOH technology leads to higher potassium residue, which makes it unusable in the polymer polyol production by the users. In contrast, FSP produced through DMC technology aligns with the process of the users and has superior consistency, which is important for the users’ competitiveness
  - d. The users are unable to use the subject goods produced by the applicant for production of polymer polyol.
  - e. The user industry depends on imports of FSP as compared to domestic FSP as it lacks requisite quality, limiting the competitiveness of downstream and export-oriented sectors.
  - f. The quality of the product supplied by the domestic industry is poor. While large manufacturers can sometimes mitigate the defects in the domestic product, majority of the downstream users which are MSMEs lack the infrastructure required to correct these inconsistencies
  - g. DMC-based FSP must be excluded from the scope of product under consideration or create a separate PCN for DMC-based FSP in the present review investigation.

- h. The product scope should be limited to FSP having molecular weight 3000 as the domestic industry does not produce FSP having molecular weight above 3000.
- i. It is submitted that Flexible Slabstock Polyol with molecular weights lower than 3000 and higher than 4000 do not fall within the PUC as notified by the Authority and must therefore be expressly excluded from the scope of the present investigation. Inclusion of such grades, despite their distinct technical characteristics, applications, and commercial markets, would be inconsistent with the Authority's product definition and would improperly broaden the investigation beyond its legally permissible scope.

## C.2. Submissions by the domestic industry

8. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
- a. The product under consideration is Flexible Slabstock Polyol with molecular weight 3000-4000.
- b. The product is used for manufacturing of foams which is majorly used in mattresses, upholstery, pillows, bolsters, transport seating and packaging.
- c. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975. Prior to February 2022, the product was imported under tariff item '3907 20' and thereafter, it was imported under tariff items '3907 29 10' and '3907 29 90'.
- d. The subject goods can be produced using KOH or DMC technology. While the applicant has used KOH technology, the producers from the subject countries have used both technologies.
- e. FSP produced using KOH technology or DMC technology is comparable and can be used interchangeably as there is no major difference in the raw materials and product process used in both technologies.
- f. The technical and chemical characteristics of the end product produced using both technologies are same, except potassium residue which is very less pronounced.

Parameter	KOH-Catalysed Polyols	DMC-Catalysed Polyols	Remarks
Molecular Weight	3000-4000	3000-4000	Same
Hydroxyl Number (mg KOH/g)	~48-56	~48-56	Same
Viscosity @ 25°C (cP)	500-700	400-600	Similar
Functionality	3 (triol)	3 (triol)	Same
Potassium Residue	5-10 ppm (after neutralization)	<1 ppm	Different
Appearance	Clear liquid	Clear liquid	Same

- g. The domestic industry is regularly supplying the subject goods to all major consumers in the country, which demonstrates that the users are using products produced using KOH and DMC technology.

Name of customer	2021-22	2022-23	2023-24	POI
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

- h. Globally, all producers, including producers in the subject countries have been using KOH technology. While certain producers have added production lines for DMC technology, such producers have not stopped the production lines for KOH technology.
- i. As against the claim that FSP produced through DMC route is of better quality, the price of imported FSP is lower than price offered by the domestic industry.
- j. The Authority in the past investigation determined that the products produced by both technologies were used by customers interchangeably.
- k. Contrary to the claim that the subject goods cannot be used for production of polymer polyol, the applicant is itself using self-produced FSP for the production of polymer polyol, which is sold in the market.
- l. EMPEYOL F3502 is the brand name for the product under consideration, for which the applicant has provided technical data sheet. The product falls under the larger class of products called “polyether polyols”.
- m. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration.

### C.3. Examination by the Authority

9. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration which was same as defined in the final finding of the original investigation.

*“ix. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol. The subject product is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter referred to as the “subject goods”).*

*x. The subject goods are classified under the category “Plastics and articles thereof” in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907 20 as per Indian Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority notes that while different ITCHS may be quoted by producers/exporters, the product description assumes primary over the ITCHS as the same is indicative.*

10. The other interested parties have argued that Double Metal Cyanide (DMC) catalyst technology is a modern and advanced process and product produced using this technology are preferred over KOH-based method. It has been claimed that DMC based FSP is preferred for its high-performance applications and reduced creation of by-products. Further, users have also claimed that they are unable to use the KOH-based FSP supplied by the domestic industry due to its poor performance.
11. On the contrary, the domestic industry has submitted that there are no differences in the product produced by either of the technologies and the products can be used interchangeably. The domestic industry has argued that there is no major difference in the production process used in either of the technologies. While the inputs such as catalysts used may differ, the major raw materials, that is propylene oxide and ethylene oxide, used in the

production process are the same. The technical characteristics of the FSP produced using KOH or DMC route are also largely similar, except with respect to Potassium residue. Further, difference of the potassium residue can be easily offset by the usage of fillers by the foam manufacturers of India. The domestic industry has also claimed that it has been regularly supplying its products to all major foam producers in the country, including those who have participated in the present investigation. In fact, the applicant is itself using the KOH-based FSP to make downstream products.

12. Similar arguments regarding difference between KOH and DMC technology have been made by interested parties in the original investigation as well. However, the Authority rejected such claims in the final finding and determined that products produced by either of the technologies were used by the customers interchangeably.
13. The Authority has examined the arguments made by all other interested parties as well as the domestic industry. With respect to the aforementioned arguments raised, the Authority notes that the present investigation is a sunset review of the anti-dumping duty imposed on imports from the subject country. The Authority has already examined and determined that there is no difference in the products produced by the domestic industry and the producer from the subject country in the original investigation. The Authority notes that this situation persists till date.
14. With respect to arguments raised against difference in technical properties between FSP produced using both technologies, the Authority notes that the production process of both routes is the same and the raw materials used are also the same. The only difference is in the catalysts used. The technical and physical properties of the end-product fall within the same range, and are inter-se comparable and substitutable, as per information submitted by the domestic industry.
15. Further, certain interested parties have argued that they are unable to use the product produced by the domestic industry due to the poor quality of the product produced using KOH technology, while the DMC based product is of higher quality. In this regard, it is noted that the domestic industry has been regularly supplying the product to its customers, who have continued to purchase its product produced using KOH technology. Thus, it is not a case that the users have ceased purchasing the product from the domestic industry on account of the product being inferior.
16. Furthermore, the price of imported subject goods, which is claimed to be produced using DMC based technology, is lower than the domestically produced FSP based on KOH-based technology.
17. Thus, the Authority notes that the use of different production processes does not lead to any difference in the final product. The subject goods manufactured using different production processes are used for the same application and in the same manner, and the characteristics of the final product manufactured using different processes are similar. The products are being interchangeably used and as substitutes to each other by the user industry. In fact, the Authority in past investigations has held that use of different production process does not render the end-product different, if such process does not result in a difference in the product characteristics and end-use. In view of the same, it is noted that there is no difference between DMC-based FSP and KOH-based FSP, and the two are like article to each other. Thus, there is no requirement to exclude DMC-based FSP.
18. Certain interested parties have argued that the scope of the product should be limited to FSP with molecular weight of 3000 only, since the domestic industry cannot produce product with molecular weight above the same. Based on the information placed on record in the form of technical data sheet and sample sales invoice, it is noted that the domestic industry has produced and sold product having molecular weight more than 3000. Thus, the argument of other parties in this regard is invalid.
19. Thus, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the final finding notification of the original investigation.
20. The Authority granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions regarding determination of the PCN methodology.

21. Certain interested parties requested that if DMC-based FSP is not excluded, then a separate PCN for DMC-based products should be created. The Authority notes that the interested parties have failed to demonstrate that there is a significant difference between the costs and resultant prices in the DMC-based FSP and KOH-based FSP. Therefore, there is no need for creation of a PCN methodology for DMC-based FSP in the present investigation.
22. The Authority notes that the product produced by the domestic industry is comparable to the product under consideration imported from the subject country in terms of physical and chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process, and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority proposes to conclude that the product produced by the domestic industry are 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

#### **D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **D.1. Submissions by other interested parties**

23. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope of domestic industry and standing.

##### **D.2. Submissions by the domestic industry**

24. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - i. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country, and thus accounts for 100% of total Indian production and is eligible to constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.

##### **D.3. Examination by the Authority**

25. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

26. The present application has been filed by Manali Petrochemicals Limited. The Authority notes that the applicant is the sole producer of subject goods in India and there is no other domestic producer of the subject goods in India.
27. The Authority also notes that the products produced by the domestic industry are like article to the imports of subject goods from the subject country.
28. Further, the Authority notes that the applicant has not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation. The applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Thus, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

#### **E. CONFIDENTIALITY**

##### **E.1. Submissions by other interested parties**

29. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to confidentiality.
  - a. The domestic industry has claimed excessive confidentiality with respect to capacity and production data for FY 2021–22 which was earlier disclosed in the final findings by the Authority.

- b. The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to NIP and net sales realization which is in violation of the trade notice 10/2018. The Authority should not have automatically accepted the confidentiality claim without evaluating the information, based on the decision of Hon'ble Supreme Court in Sterlite Industries (India) Ltd. v. DA; CESTAT in H&R Johnson (India) Ltd. v. DA; and WTO Appellate Body in EC – Certain Iron or Steel Fasteners from China.
- c. The exporter has provided details of all third country sales in view of full compliance and transparency. The disclosure of details of third country sales would be detrimental to the interests of the exporter, and have been claimed confidential.
- d. The exporter has provided names of all affiliates involved in sales of the subject goods and no other affiliate is involved in the sales of the subject goods in India.

### **E.2. Submissions by the domestic industry**

30. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
  - a. SABIC has failed to provide a non-confidential summary of the details regarding appropriate third country and the basis of selecting the appropriate third country for calculation of normal value.
  - b. The domestic industry has not sought disclosure of complete third country sales of the exporters, but at the very least, the exporter should disclose if it is claiming normal value based on third country sales.
  - c. SABIC has failed to disclose the details of affiliates located in India and the activities performed by such entities. Such information is available on the public domain.
  - d. The arguments of the interested parties regarding confidentiality claims are highly belated and cannot be accepted.
  - e. As a single applicant, the domestic industry has provided figures pertaining to capacity and production as trend in the non-confidential version of the application, in line with Trade Notice 10/2018.
  - f. The non-injurious price of the domestic industry is highly confidential, and can be severely detrimental to the competitive interests of the domestic industry, in its negotiations with the customers. Thus, the same cannot be disclosed.

### **E.3. Examination by the Authority**

31. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7) of the Rules.
32. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provide as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information*

33. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties provided information on a confidential basis were directed to provide sufficient non confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1. Submissions by other interested parties**

34. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- a. The petition does not satisfy the requirements of Article 5 of the Anti-Dumping Agreement and Rule 5 of Anti-Dumping Rules as it lacks evidence with respect to alleged dumping, injury and causal link. The applicant has constructed normal value based on its cost of production, which is contrary to para 1 of Annexure I and has only provided evidence for adjustments towards ocean freight. An initiation based on incorrect application of legal provisions is void ab-initio and such investigation must be terminated immediately, as held in *Chairman-Cum-M.D., Coal India & Ors vs Ananta Saha & Ors*, (2011) 5 SCC 142.
  - b. The domestic industry has been a beneficiary of anti-dumping duties for a long time, restricting imports of FSP from various countries and includes withdrawal of application in some cases demonstrating that the domestic industry has received adequate protection since 2001.
  - c. Despite prolonged duration of duties, the domestic industry has failed to demonstrate improvement in production, technology and capacity, and have further failed to reduce costs, improve efficiency and competitiveness.
  - d. The import data submitted by the applicant is unreliable as it does not align with the import data published by the Authority in the original final findings. Even if the investigation was initiated based on imports from DGCI&S, the application was deficient and should not have been accepted and highlights the frivolity and internal inconsistencies of the present proceedings.
  - e. The association's membership can be publicly verified, and any attempt by the applicant to cast doubt on the credibility of the association is unwarranted, given that the applicant itself is a member of the association.
  - f. The Authority must provide the user industry with import data in the format and manner in which it was placed on record. Reliance was placed on *Exotic Décor Pvt. Ltd. vs Designated Authority* in this regard.
  - g. The Authority is requested to use DGCI&S data to determine injury as against the inflated margins claimed by the applicant.
  - h. The DI did not furnish actual home-market data, third-country prices, or a properly supported constructed normal value. The DI merely relied on its *own* Indian cost of production to build a constructed NV — a method unsupported by law.
  - i. Transaction-wise details of exports to third countries are confidential and not required to be disclosed in terms of Trade Notice No. 10/2018.

### **F.2. Submissions by the domestic industry**

35. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
- a. Claims of misuse of trade remedy investigation are misplaced, as it is the foreign producers that are abusing fair market.

- b. Contrary to the argument of the other interested parties, the Authority found that the subject imports caused injury to the domestic industry and there was a need to continue duties in past investigations, except where the applicant withdrew its application considering temporary relief against dumping.
- c. The applicant has relied imports sourced from third parties, while the Authority relies on DGCI&S data, which may have led to the differences in import volumes.
- d. The association has not provided list of its members, or demonstrated which of its members would be affected by the measures. Therefore, it has not demonstrated its status as an interested party. The association must also demonstrate that it was validly authorized to participate.
- e. The applicant provided normal value and export price for the subject country based on the information that was reasonably available to it at the time of filing of the application.

### **F.3. Examination by the Authority**

36. With regard to the submission that the petition does not satisfy the requirements of Article 5 of the Anti-Dumping Agreement and Rule 5 of Anti-Dumping Rules as it lacks evidence with respect to alleged dumping, injury and causal link, the Authority notes that the present review was initiated based on prima facie examination of the evidence provided and duly satisfying itself on the accuracy and adequacy of the evidence provided by the applicant as was reasonably available to it at the time of initiation.
37. With regards to the submission that the applicant is misusing trade remedial measures and has been a beneficiary of trade remedial investigations since last two decades, the Authority notes that all the investigations have been conducted based on detailed examination of evidence submitted by all parties and recommendation for imposition / continuation of duties has been made only after examination of dumping, injury and causal link, wherever relevant.
38. It has been argued by certain interested parties that despite long duration of duties, the domestic industry has failed to demonstrate improvement in production, enhancement in capacities and cost efficiency. In this regard, it is noted that in an anti-dumping investigation, the Authority is required to examine where the product under consideration is being dumped into the country and that such dumped imports are causing injury to the domestic industry. The fact that the exporters are dumping the subject goods in the country is a material fact, irrespective of whether the industry has increased capacities or not.

With regards to the submission that the Authority has not made available the import data in the format and manner prescribed to the user industry, the Authority notes that the DGCI&S transaction wise import data is not available in the public domain and the same cannot be shared with any party under the current legal provisions.

39. Certain interested parties have claimed that the data used by the applicant is not reliable and thus, has resulted in the inflated claims of margins. In this regard, it is noted that the applicant has relied on import data sourced from market sources in the application filed. However, the Authority has relied upon the import data as per DGCI&S for the purpose of this investigation. Further, the dumping margin for the cooperating exporters would be based on the data submitted by them and duly verified by the Authority. Accordingly, the reliability of the import data used by the applicant in its application is not material

## **G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

### **G.1. Submissions by other interested parties**

40. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
  - a. The Authority is requested to calculate normal value and export price based on information provided by Sadara and not on the basis of claims made by the domestic industry which are inconsistent with Section 9A of the Tariff Act.

- b. The DI's claimed adjustments—such as for ocean freight, insurance, and commissions—are not accompanied by any underlying evidence. SABIC and SAPPL provided information regarding third country exports as a matter of abundant caution. Transaction-wise export details to all third countries have been provided.
- c. There is no basis for disregarding the costs reported by Sadara since the Authority has already established in previous investigations (such as FSP and TDI) that Sadara's procurement from SABIC are at arm's length.
- d. Several WTO Panel and Appellate Body reports have held that the costs reported in the records of an exporter cannot be disregarded.
- e. The applicant's reliance on US-OTCG is wrong since even in that investigation, the Panel did not permit the use of international prices to determine whether purchase prices were at arm's length.
- f. Manali has claimed that Sadara has sourced two major raw materials i.e. propylene and ethylene, from SABIC, a related entity. This claim is factually incorrect since Sadara has not sourced any of these inputs from SABIC. Accordingly, the Normal Value for Sadara should be computed based on the cost of production claimed in the questionnaire response.
- g. The Domestic Industry has claimed that import volume from Saudi Arabia is 1,11,154 MT. However, the actual export volume by Sadara (the sole producer in KSA) during the POI, as per evidence on record is merely 53314 MT. Thus, the volume of export as well as the export price claimed by Manali is incorrect and misleading.
- h. The data concerning import of FSP portrayed by Manali is incorrect, is further confirmed from bare comparison of data in the application and the earlier final findings issued by the DGTR. As per earlier final findings issued by the DGTR concerning exports from China and Thailand, the overall import volume of FSP during 2021-22 was determined as 91,155 MT. On the contrary, Manali in the present application has claimed import volume as 161,121 MT. Thus, it is evident that data submitted by Manali is incorrect and liable to be rejected.

## **G.2. Submissions by the domestic industry**

41. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
  - a. The price of inputs purchased by Sadara from its related parties must be rejected unless the producer can demonstrate that such transactions were on an arm's length basis. Only if such information is found to be appropriate and accurate, the same may be used for determination of dumping margin for the exporters.
  - b. If the exporter is unable to demonstrate that inputs purchased from the affiliates were at an arm's length, the cost of production for the producer should be determined based on price of exports of propylene and ethylene from Saudi Arabia based on Trade Map data.
  - c. The Authority should examine the claim of normal value based on third country exports considering the representative volume of exports to such country and the exports being in the ordinary course of trade.
  - d. The Authority must verify the information submitted by the exporters, particularly with respect to purchase of inputs from affiliated parties. Only if such information is found to be appropriate and accurate, the same may be used for determination of dumping margin for the exporters.
  - e. The fact that the Authority found dumping in previous investigations shows that the dumping is not attributable to the technology or level of integration of the domestic industry, but the unfair pricing practices adopted by the foreign producers.

- f. Contrary to claim of interested parties, the domestic industry has not claimed dumping based on positive price undercutting.

### G.3. Examination by the Authority

42. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

*“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

*ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”*

43. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:
- a. Sadara Chemical Company, Kingdom of Saudi Arabia
  - b. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Kingdom of Saudi Arabia
  - c. SABIC Asia Pacific Pte. Ltd., (SAPPL), Singapore
  - d. Dow Chemical International Private Limited (DCIPL) Dubai Branch, UAE
  - e. Dow Saudi Arabia Marketing B.V., (DSAPM BV, Netherland
  - f. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore

#### G.3.1. Normal value for Saudi Arabia

##### Normal value for Sadara Chemicals Limited

44. It is noted Sadara is the producer of subject goods from Saudi Arabia engaged in domestic sales of subject goods as well as exports to India through related entities namely Dow Marketing, Dow Singapore, SABIC and SAPPL. Sadara is a limited liability company existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia.
45. The subject goods produced by Sadara were sold to Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), which has then resold the product in the domestic market to unaffiliated customers. There were no direct domestic sales by Sadara during the POI.
46. The Authority has conducted desk verification of the data submitted by the exporter. It is noted from the response that during the period of investigation, SABIC has sold \*\*\* MT of goods in domestic market having an invoice value of \*\*\* million SAR in the domestic market.
47. For computing the Normal Value, all domestic sales transactions by SABIC to unrelated customers were examined with reference to the cost of production determined by the Authority to assess whether the domestic sales were in the ordinary course of trade or not. The Authority conducted the ordinary course of trade test to

determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the Domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value.

48. Based on the ordinary course of trade test, it is noted that there are no profitable domestic sales during the POI for computing the normal value. Accordingly, the normal value has been considered based on the cost of production of PUC as determined by the Authority after including SGA and notional profit. The Normal value determined as above is mentioned in the dumping margin table.

#### Normal value for other producers/exporters in Saudi Arabia

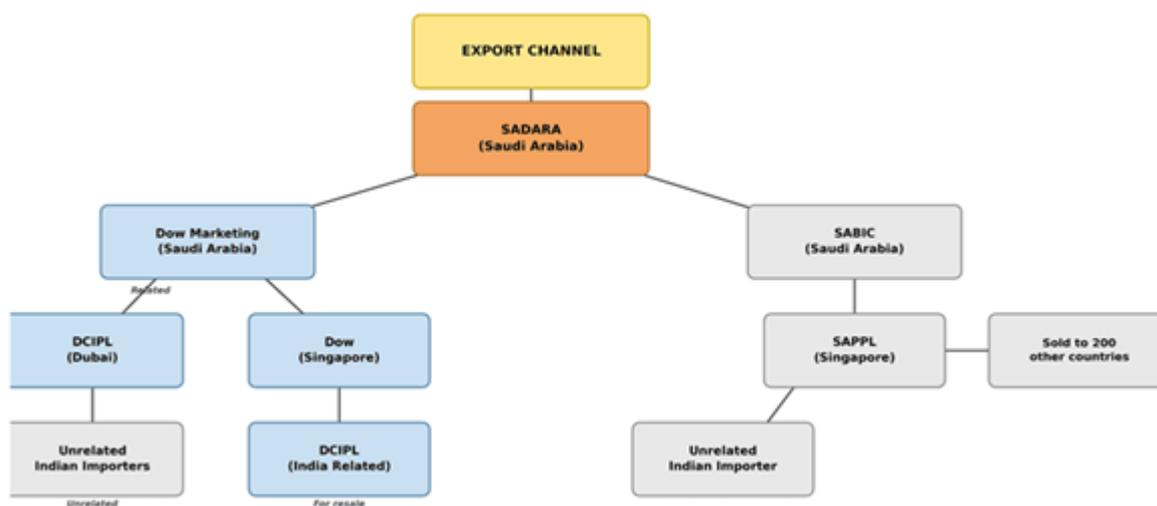
49. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Saudi Arabia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

#### G.3.2. Export price for Saudi Arabia

**Export price for Sadara Chemical Limited, Saudi Basic Industries Corporation, SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. Dow Chemical International Private Limited, Dubai Branch, UAE Dow Saudi Arabia Marketing B.V., Netherland and Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore**

50. It is noted from exports to India, M/s Sadara sells the entire quantity of the subject goods to Dow Saudi Arabia Product Mktg BV (“Dow Marketing”) and Saudi Basic Industries Corporation (“SABIC”). For exports to India, Dow Marketing raises invoice on Dow Singapore which in turn sells to Dow Chemical International Pvt. Ltd. (DCIPL) who has captively consumed the product.

51. The export channel can be understood from the flowchart given below:



52. For arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered adjustments on account of freight, credit cost and other post factory expenses from the invoice price of the producer (Sadara). Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping margin table below.

#### Export price for other producers/exporters in Saudi Arabia

53. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Saudi Arabia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

#### G.3.3. Dumping margin

54. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

**Dumping Margin Table**

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
<b>Saudi Arabia</b>						
	Sadara Chemical Company	***	***	***	***	90-100
	Any Other	***	***	***	***	100-120

### H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

#### H.1. Views of other interested parties

55. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- The volume of imports in absolute and relative terms has declined during the period of investigation which contradicts the claim of injury made by the applicant. Further, as the demand continued to increase, the imports were necessitated to meet the demand.
  - The Authority should calculate price undercutting for imports from Saudi Arabia, after taking into account the anti-dumping duty in place.
  - It is critical to highlight that the alleged injury to the Domestic Industry during the current review period is not attributable to imports from Saudi Arabia, but rather to continued low-priced imports originating from Thailand and China.
  - During the period of investigation, the landed value of Saudi Arabia declined while selling price of the domestic industry increased, showing absence of correlation between landed value and cost and sales realization of the domestic industry.
  - The losses earned for product under consideration are in line with overall decline in profitability of the company.
  - The market share of domestic industry should be calculated after considering imports from all sources.
  - As per the decision in Nirma Ltd. vs. Union of India, the parameters of threat of injury are required to be examined in a sunset review for the purpose of likelihood analysis. Such parameters have not been examined in the present case. In any case, the threat parameters are not met in the present case.
  - The comparison with base year is inappropriate as COVID-related disruptions enabled Manali to earn abnormal profits. Moreover, the Annual Reports and investor calls of the domestic industry also confirm that 2020-21 and 2021-22 were exceptional years, with record sales, profitability, and increased returns

- i. Manali has planned investment in two plants and has approved expansion in West India. Its low debt-to-equity ratio of 0.14:1 shows strong financial capacity, confirming that its ability to raise capital has not been adversely impacted.
- j. The prices of the domestic industry were suppressed as it was unable to cover its high costs which were affected by high raw material prices, and self-inflicted internal disruptions such as acquisition and depreciation burdens.
- k. By excluding Singapore from the scope of the review, the applicant has effectively narrowed the injury analysis to imports from only one country—Saudi Arabia—while disregarding significant import volumes from Singapore that are admittedly priced below the proposed Non-Injurious Price (NIP). This selective treatment fundamentally distorts the factual matrix and leads to an inflated, misleading depiction of injury.
- l. The Authority has consistently held that injury must be assessed in the context of the totality of dumped imports from all relevant sources. Selectively targeting one country while ignoring equally or more injurious imports from another major source not only undermines the credibility of the injury assertion but renders the causal link analytically unsound.
- m. Injury to the domestic industry is caused due to imports from China and Thailand as well as Singapore, and such injury cannot be attributed to imports from Saudi Arabia.
- n. Despite significant imports from Singapore, the applicant failed to timely file an application for continuation of duties from Singapore, which has resulted in inflated injury and erroneous causal link. Non-imposition of duty on Singapore would lead to trade diversion, which would nullify the impact of duties.
- o. Present anti-dumping duties have addressed dumping from Saudi Arabia, while significant imports from China and Thailand have caused injury. As admitted by the applicant in its annual report, imports from such countries increased in anticipation of duties
- p. While the production has declined by 41 points, export sales have declined by 88 points. Despite getting better prices in export markets, the applicant has reduced export sales and its export price declined over the injury period in line with the import price. Further, during the period of investigation, the export price remained constant despite claimed increase in costs.
- q. The decline in production is not due to imports since - (a) the production of other non-subject goods has also declined; and (b) the domestic industry had the option to produce for exports, but deliberately chose to curtail production.
- r. Limited production capacity of the domestic industry as compared with major global players, prevents it from achieving economies of scale, resulting in higher per-unit costs. Further, the applicant is not backward integrated and is dependent on other suppliers for major raw materials. Lastly, the applicant is located at a distance from suppliers of PO and EO, which adds to incompetiveness.
- s. The applicant faced decline in production of the subject goods due to disruptions at the plant due to cyclone Michaung and not due to subject imports.
- t. The applicant has increased captive consumption of the subject goods and reduced domestic sales.
- u. Price undercutting is not indicative of dumping but is due to high cost of the domestic industry resulting from obsolete technology and lack of backward integration.
- v. The FSP supplied by the domestic industry is inferior due to the outdated KOH method, while global producers use advanced DMC technology. The resultant price differences and injury reflect quality issues and market preferences and not dumping

- w. For determination of NIP, the cost of production of the applicant must be suitably adjusted to account for technical difficulties faced and extraordinary costs incurred by the applicants. The Authority when determining the NIP shall consider the operational and capacity constraints faced by the Applicant during the injury assessment period, and any extraordinary or non-recurring expenses must not be considered when considering the NIP
- x. Since Manali has bought PO from its affiliate TPL, the global prices of raw materials should be considered for arm-length price comparison.
- y. DI's own annual report confirms that operations were severely disrupted due to Cyclone Michaung, which damaged equipment, halted production for an extended period, caused inventory loss, and led to significant repair expenses.
- z. The DI progressively diverted greater quantities of its output for captive use (indexed rise from 100 to 364), which naturally reduced its domestic sales.
- aa. A substantial proportion of DI's purchases and sales were with related parties (28% of raw materials and substantial output). Such transactions may not reflect market prices and could distort both cost and profitability.

## H.2. Views of the domestic industry

56. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
- a. The volume of subject imports has increased significantly over the injury period, in absolute terms as well as in relation to Indian production and consumption. Despite decline in volumes of imports in the period of investigation, the volume of imports has remained significant.
  - b. The rate of increase in imports has outpaced the rate of increase in demand in the country. In fact, the subject imports are in excess of the demand-supply gap in the country.
  - c. The landed price of the subject imports has declined sharply over the injury period, despite no material change in the price of major raw material, propylene.
  - d. The mark-up of landed prices over raw materials has declined over the injury period.
  - e. The costs of the domestic industry in absolute terms have declined, including fixed costs and cost of utilities. However, due to dumping, the production has reduced, and as a result, the per unit cost is higher.
  - f. The change in selling price and landed price during the period of investigation cannot be seen in isolation and must be seen in the context of the cost of sales.
  - g. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry, even after addition of anti-dumping duty in the landed price.
  - h. The subject imports suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
  - i. The volume of imports have increased in the post-POI period, while the prices of such imports have declined further.
  - j. The sales of the domestic industry declined significantly due to increasing demand for low-priced subject imports. As a result, the domestic industry was forced to curtail its production and its production volumes declined.
  - k. Despite a demand-supply gap, the domestic industry was operating at less than 50% capacity utilization during the period of investigation.
  - l. While the captive consumption of the domestic industry increased over the period, such consumption was less than 3% and 4% in relation to production and sales of the domestic industry respectively.

- m. As the demand for dumped imports increased over the period, the market share of the subject imports also increased, while the market share of the domestic industry was woefully low.
- n. The domestic industry faced significant accumulation inventories, which increased by 637% over the injury period.
- o. Since 2022-23, the domestic industry has been incurring significant financial losses including cash losses, and has earned negative returns on its investment.
- p. Reference to debt-equity ratio of the company as a whole is not appropriate, as the injury analysis is required to be conducted with reference to the like article.
- q. Contrary to the claim that the domestic industry has not shown any improvement despite duties, the domestic industry was unable to increase capacities or production or employ new technology due to continuous onslaught of dumped imports.
- r. The domestic industry is not required to show improvement in performance in face of unfair dumping. Dumping that is an unfair pricing practice, and the domestic industry cannot be expected to take steps to offset such pricing practices.
- s. The exporters in the subject country have a tendency to dump evidence from dumping in the original investigation and continued dumping the present case.
- t. The volume of subject imports has continued to increase despite duties in place.
- u. While the volume of exports from Saudi Arabia to other countries has increased marginally, exports to India have increased significantly.
- v. The price of subject imports has continued to decline sharply.
- w. The volume of imports has continued to increase in the post-POI period, while the prices of such imports have declined.
- x. The subject imports are entering at prices that are likely to further depress the prices of the domestic industry.
- y. The domestic industry is suffering injury and is in a fragile situation, which is likely to be aggravated in case of expiry of duty.
- z. India is a lucrative market for the exporters considering the increasing demand, and expiry of duties would allow the exports to divert all their exports to India.
- aa Provisions of Para (vii) of Annexure II (Rejoinder submissions) are applicable in case of claim of recurrence of injury in absence of duties, which is not the case of the domestic industry.
- ab Injury to the domestic industry has not been caused by any other factor.
- ac With respect to claim that the domestic industry is not backward integrated, the applicant cannot be faulted for not having a backward integrated plant since the same would require a multi-million investment for setting up a refinery, which is not feasible.
- ad Injury to the domestic industry must be examined as it exists and factors inherent to the industry cannot be considered as causing injury, as held by the Appellate Body in EU – Biodiesel (Argentina), in the case of Nippon Zeon Co. Ltd. vs. Designated Authority, and accepted by the Authority in various investigations.
- ae The subject imports must be one of the causes of injury and not the only cause of injury, as held in EC – Tubes and Pipes, U.S. – Hot-Rolled Steel Products and U.S. – Salmon.
- af Imports from Singapore are priced higher than the subject imports, and such imports have not caused injury to the domestic industry. In fact, even if anti-dumping duty is added to the price of imports from Saudi Arabia, the price is lower than the price of imports from Singapore.

- ag The landed price of imports from Singapore, after accounting for anti-dumping duty, did not undercut the prices of the domestic industry during the period of investigation. Thus, such imports did not cause injury to the prices of the domestic industry during the period of investigation. By contrast, even after accounting for anti-dumping duty, the price of imports from Saudi Arabia were much lower than the prices of the domestic industry.
- ah Despite adjusting the total capacity in the injury analysis for removing the effects of shutdown caused due to cyclone, the domestic industry faced significantly underutilized capacities. Further, since ab variable costs account for more than 80% of the total cost, increased costs due to shut down could not have caused injury to the domestic industry.
- ai Performance of the domestic industry in other products is irrelevant in an anti-dumping investigation as per para (vi) of Annexure II.
- aj The product under consideration is the price setter for the market and a decline in the sales of the subject goods directly lead to decline in the sales of non-subject goods, forcing the domestic industry to curtail overall production.
- ak The export sales of the domestic industry are sporadic, and negligible compared to the production, at less than 2% of production. No inference can be drawn based on such low volume of exports. The primary focus of the domestic industry has remained on domestic market.
- al The major reason for decline in the overall profitability of the company was sharp increase in cheap imports which eroded the market share of the applicant.
- am Contrary to the claim that the domestic industry earned abnormal profits in 2021-22, the domestic industry earned profits due to market vacated by the dumped imports. However, the profitability in the last quarter declined as imports resumed.
- an Contrary to the arguments of the other interested parties, the domestic industry did not face any raw material supply shortage.
- ao Even if the domestic industry arguendo faced shortage of raw material, it does not explain the price pressure faced by the domestic industry.
- ap Inputs from the affiliated party have been purchased at an arm's length prices, and are priced below global import prices of propylene oxide. However, the domestic industry has no objection should the Authority find it more appropriate to consider global import prices.
- aq The domestic industry has submitted its capacity information after reducing the effect of the shutdown. Further, the domestic industry has not claimed any extraordinary or non-recurring expenses as a part of its cost of production.

### H.3. Examination by the Authority

57. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

58. Certain interested parties have argued that the comparison of the performance of the domestic industry with the base year is inappropriate as the domestic industry was able to earn abnormal profits during this period due to Covid-related disruptions. The domestic industry has disputed the same and has claimed that it was able to earn profits only because it was able to sell its product at remunerative prices in the absence of the dumped imports. It is noted that in 2021-22, the volume of dumped imports from all sources was the lowest during the injury period. At the same time, the sales of the domestic industry were the highest over the entire injury period. Thereafter, the volume of dumped imports increased over the injury period, while the sales of the domestic industry declined. This establishes that the domestic industry was able to sell its products in 2021-22 when the dumped imports vacated the market, and earned profits. However, it has faced losses thereafter as it has been unable to sell its product as dumped imports command the majority of the market.
59. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

### H.3.1. Volume effect of the dumped imports

#### a) Assessment of demand / apparent consumption

60. The Authority, has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Excluding Captive					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	81	44
Imports from subject country	MT	31,923	32,882	38,817	54,791
Imports from other countries	MT	67,643	86,793	1,02,260	93,982
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	132	133
Including Captive					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	82	45
Imports from subject country	MT	31,923	32,882	38,817	54,791
Imports from other countries	MT	67,643	86,793	1,02,260	93,982
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	132	133

61. The Authority notes that the demand for the subject goods in India has increased year on year over the injury period and was the highest in the period of investigation.

**b) Import Volumes from the subject countries**

62. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI & S data. The import volumes from subject country during the injury period are as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from subject country	MT	31,923	32,882	38,817	54,791
Imports from other countries	MT	67,643	86,793	1,02,260	93,982
Total Imports	MT	99,566	1,19,675	1,41,076	1,48,773
Subject imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	143	291
Consumption/Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	92	130
Total imports	%	32%	27%	28%	37%

63. The Authority notes that:

- i. The volume of imports from the subject country has increased year on year over the injury period.
- ii. Imports in relation to production in India have increased significantly over the injury period and were the highest in the period of investigation.
- iii. Imports in relation to consumption in India has also increased over the injury period, except slight decline in 2023-24. Thereafter, it increased again in the period of investigation.
- iv. While the share of subject imports in total imports was 32% in the base year, the same has increased to 37% in the period of investigation.

64. The Authority further notes that the subject imports have increased at a pace much more than the rate of increase in demand in India. While the demand has increased by 33% over the injury period, the subject imports have increased by 72%.

A

**H.3.2. Price effect of the dumped imports**

65. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports

as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

**a) Price undercutting**

66. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

Particulars	Unit	POI
Net sales realization	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	20-30%

67. The Authority notes that the subject imports are priced significantly below the selling price of the domestic industry. The price undercutting from the subject country is positive and significant.

**b) Delta of landed price over raw material cost of domestic industry**

68. The domestic industry has claimed that despite any significant fluctuation in the cost of raw materials, the landed price has continued to decline and was even lower than the cost of materials. It is noted that the the raw material cost of the domestic industry has remained unchanged over the injury period. However, the landed price of imports has declined by 55% during this period. Further, while the subject imports were priced almost double the raw material cost of the domestic industry in 2021-22, the delta has reduced significantly. In 2023-24 and the period of investigation, the subject imports were priced below the cost of raw materials of the domestic industry.

Particular	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Raw Material Cost	₹/MT	***	***	***	***
Landed Price	₹/MT	2,18,484	1,29,475	1,01,943	98,230
Mark up	₹/MT	***	***	***	***
Mark up	%	98%	8%	-6%	-11%

**c) Price suppression/depression**

69. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which

otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	98	117
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	64	66
Landed price	₹/MT	2,18,484	1,29,475	1,01,943	98,230
Trend	Indexed	100	59	47	45

70. The Authority notes that in 2022-23, the cost of sales increased. However, the selling price of the domestic industry declined due to sharp decline in the prices of subject imports. Thereafter, the cost of sales and selling prices of the domestic industry and landed prices of imports have declined. The decline in landed prices was higher than the decline in cost of sales of the domestic industry. During the period of investigation, while the cost of the domestic industry increased by 17%, its selling price has increased by only 2% due to continuous decline in the landed prices of imports. An examination of the trends from the base year shows that while the cost of sales of the domestic industry has increased, the selling price of the domestic industry has declined by 34% pursuant to the decline in the landed prices by 55%. It is, therefore, noted that the imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.

### H.3.3. Economic parameters of the domestic industry

71. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

#### a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

72. The capacity, production, sales and capacity utilisation of the domestic industry over the injury period were as below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100

Available Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	86
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	85	59
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	102	65
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	81	44
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	37	25	12
Captive Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	181	296	364

73. The Authority notes that:

- a. The installed capacity of the domestic industry has remained stable throughout the injury period.
- b. The production and sales of the domestic industry have declined over the injury period. As a result of significant decline in the sales of the domestic industry, the domestic industry was forced to curtail its production.
- c. The capacity utilisation has also declined significantly over the injury period. During the period of investigation, the domestic industry was operating with only half of its capacities.

74. It has also been argued that decline in production is linked to plant shutdown faced due to cyclone. The domestic industry submits that it has faced significant underutilized capacities despite adjusting the total capacity for removing the effects of the plant shutdown. The Authority notes that the domestic industry has submitted data after excluding the impact of the plant shutdown due to cyclone. Even after excluding the impact, the capacity utilization of the domestic industry is less than 50%. Therefore, a decline in the performance in the period of investigation cannot be attributed to the plant shutdown.

75. Further, it has been argued that the captive consumption of the subject goods has increased, however the domestic sales of the domestic industry has declined. In this regard, the Authority notes the volume of captive consumption has remained low and accounted for a negligible share as compared to the total production volume and total volume of domestic sales of the domestic industry.

#### b) Market share

76. Market share of the imports and domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Market Share excluding captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85.14	61.42	33.33
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88.11	92.12	129.52
Other imports	%	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	109.85	114.6	104.9
Market Share including captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85.38	62.06	34.07
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88.07	92.04	129.35
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109.73	114.45	104.71

77. It is noted that the domestic industry has captively consumed the subject goods. Accordingly, the market share has been determined-

- including captive consumption by the domestic industry and
- excluding captive consumption by the domestic industry.

78. The Authority notes that the market share of the domestic industry has declined over the injury period. However, the market share of the imports from other countries as well as of subject imports have increased in POI as compared to base year.

79. With regard to the submission that the market share of the domestic industry must be calculated after considering the imports from other countries, the Authority notes that the market share has been calculated on the basis of total product available in the market including imports from other countries.

**c) Inventories**

80. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	247	737

81. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period. While there is ample demand in India, the domestic industry has suffered due to accumulation of inventories.

**d) Profitability, cash profits and return on capital employed**

82. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	98	117

Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	64	66
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-30	-22	-63
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-30	-17	-28
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-25	-14	-23
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-50	-41	-68

83. The Authority notes the following:

- a. The domestic industry earned sufficient profits during till 2021-22. However, the profitability of the domestic industry declined in 2022-23. The domestic industry suffered significant losses as it reduced its prices in order to recover its market share.
- b. During the period of investigation, the profitability of the domestic industry deteriorated as compared to the base year.
- c. The domestic industry has also suffered deterioration in cash profits over the period.
- d. The domestic industry has faced a significant decline in its return on capital employed. While the domestic industry earned a healthy return till 2021-22, its return on investment declined in 2022-23 and was negative in the period of investigation.
- e. With regard to the submissions by the other interested parties that losses in past investigation have been converted to profits in present investigation, it is noted that during the POI (Oct, 2021 to Sep, 2022) of the previous investigation, an important ingredient namely, propylene oxide, which was used for manufacture of PUC was procured domestically from related party (at arm's length price) and also produced captive. The methodology for transfer price during the previous injury period was based on domestic procurement (i.e., from related party at arm's length price). This resulted in higher raw material price, leading to higher cost of sales and consequential losses for PUC. The same practice was followed for all the four years of injury period for even comparison. However, since the input raw material was considered at market price, no capital employed for such captive input was provided for determining return on capital employed. In the present investigation period, during POI (Oct, 2023 to Sep, 2024), the domestic industry manufactured propylene oxide captive and same was transferred at cost. Therefore, for the whole current injury investigation period, (which also includes the common FY 2020-21 with previous investigation period), same practice was required to be followed for even comparison. Thus, the transfer price for the captive input, namely, propylene oxide, is considered at cost for ascertaining the cost of production of the PUC. Further, capital employed for such captive input has been added to the capital employed for PUC for allowing return on capital employed.

**e) Employment, productivity and wages**

84. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Employees	Nos.	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	100	100	100
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	85	59
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	42	88

85. The Authority notes that the number of employees and productivity per employee have remained same over the injury period. However, the productivity per day and wages paid to employees have declined over the injury period after slight increase in 2023-24. The domestic industry has not claimed injury on this account.

**f) Growth**

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	%	-	-	-	-
Production	%	-	-1%	-14%	-31%
Domestic sales	%	-	-1%	-19%	-46%
Profit / (loss) per unit	%	-	-130%	-29%	193%
Cash profits	%	-	-125%	-45%	65%
Return on capital employed	%	-	-150%	-19%	67%

86. The Authority notes:

- a. The capacity of the domestic industry has not shown any change over the injury period.
- b. The domestic sales have shown a negative growth as the domestic industry.
- c. The profitability parameters have shown significant negative growth as the domestic industry have continued to face losses and earned negative returns.

**g) Factors affecting prices**

87. It is noted that the domestic industry has not been able to increase its prices in relation to the increase in cost of sales. The subject imports have forced the domestic industry to sell the goods below its costs. Further, the subject imports have significantly undercut the domestic prices, creating a strain on the prices of domestic industry, which has resulted in a decline in profitability and return on capital employed. Thus, the subject imports have affected the prices of the domestic industry.

**h) The magnitude of dumping**

88. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject country. The dumping margin is positive and significant.

**I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY**

89. The present investigation is a sunset review of duties on the imports of the product under consideration from Saudi Arabia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties, and has noted as below.

**I.1.1. Continued dumping despite the existence of anti-dumping duty**

90. It is noted that the dumping margin of the subject country was 20-30% in the previous investigation, which has now increased to 90-100%. The exporters in the subject country have continued to dump the subject goods into the country despite anti-dumping duties being in place. The continued dumping demonstrates that there is likelihood of continued and aggravated dumping in the event of expiry of duty as the dumping margin continues to remain positive and significant.

**I.1.2. Increase in imports of the subject goods despite duties**

91. The import data clearly shows that there is significant dumping of the subject imports from Saudi Arabia, despite anti-dumping duties in place. The volume of imports has increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Therefore, there is likelihood that the volume of subject imports will further increase in the event of expiry of duties.

**I.1.3. Exports to India vis-à-vis exports to third country**

92. The Authority examined the data submitted by Sadara Chemical Company in its response. It is noted that the volume of exports to India has increased at a higher rate than the volume of exports to other third countries by the exporter from the subject country.

**I.1.4. Likely suppressing and depressing effect on prices of the domestic industry**

93. The data on record shows that the prices of imports have continuously declined over the injury period and have undercut the selling prices of the domestic industry. As a result, the domestic industry was forced to reduce its prices below its costs in order to compete with the imports prices. Further, the subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry despite anti-dumping duties in place. Therefore, in case the duties are allowed to expire, the exporters will be motivated to further decline its prices and cause injury to the domestic industry.

**I.1.5. Domestic industry is vulnerable**

94. The subject imports have continued to cause injury to the domestic industry despite imposition of duties. The volume and profitability parameters of the domestic industry have declined over the injury period due to presence of cheap imports. This is despite the anti-dumping duties being in place. Thus, in case the duties are allowed to expire, the subject imports will have a further adverse impact on the performance of the domestic industry.

**I.1.6. Trend of volume and price of subject imports post the period of investigation**

95. The domestic industry has submitted the information regarding performance of the domestic industry post the period of investigation. In this regard, the Authority notes that the situation for the domestic industry has worsened in the period subsequent to the period of investigation. The volume of imports from subject country have continued to increase and the prices of the subject imports have continued to decline. This implies that the exporter will further be motivated to dump its article into India, in case of cessation of duties.

**I.1.7. India is lucrative market**

96. The Authority notes that India continues to be a lucrative market for the dumped imports. As noted hereinabove, the demand for the subject goods have continued to increase and will continue to increase since the subject goods is a commodity product and is highly price sensitive. The cessation of duties will further motivate the exporters to dump its goods in India.

**J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CAUSAL LINK****Non-attribution analysis**

97. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

**a. Volume and value of imports from third countries**

98. It is noted that the subject goods are being imports in significant quantities from other countries such as China, Thailand, Singapore, USA, Japan, Korea, Taiwan. The Authority notes that there is a parallel anti-dumping investigation being conducted against imports from China and Thailand. Moreover, imports from other countries are priced higher than the prices from the subject country.
99. Certain interested parties have argued that imports from countries like Singapore, China and Thailand have caused injury to the domestic industry and not the subject goods. The Authority notes that the imports from China and Thailand are already subject to a parallel anti-dumping investigation.

**b. Contraction in demand**

100. The demand for the subject goods has increased over the injury period and was the highest during the period of investigation. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

**c. Pattern of consumption**

101. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

**d. Conditions of competition and trade restrictive practices**

102. The Authority notes that there are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have cause injury to the domestic industry.

**e. Developments in technology**

103. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.

**f. Productivity**

104. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has more or less remained constant. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

**g. Export performance of the domestic industry**

105. The injury information examined herein above relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.
106. Certain interested parties have argued that the export sales of the domestic industry have also declined, despite the industry getting prices in the export market. In this regard, it is noted that the present investigation is limited to examination of the impact of dumped imports on the like article sold by the domestic industry in the domestic market, and whether expiry of current duties would result in continuation of dumping and injury. Thus, the performance of the domestic industry with respect to its exports is not material in the present investigation. Further, the volume of exports by the domestic industry is significantly low when compared to its production volume.

**h. Performance of other products**

107. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

**i. Plants of domestic industry not backward integrated and use of obsolete technology**

108. With regards to the submissions that the injury to the domestic industry has been caused due to its own inefficiencies such as lack of backward integration in plants, usage of obsolete technology and depreciation burdens, the Authority notes that such factors are inherent to the industry and have remained unchanged. Thus, it cannot be said that such factors have now started causing injury to the domestic industry.

**j. Impact of Michaung cyclone**

109. It has been argued by certain interested parties that the domestic industry may have suffered injury due to shutdowns suffered on account of Michaung Cyclone in the region. It is noted that the domestic industry segregated the impact of shutdown faced due to cyclone, and has reduced its available capacities in order to remove the impact of such shutdown. However, despite making adjustment to the capacity to offset the impact of cyclone-related shutdown, the domestic industry has faced significant underutilization and its production continued to decline as its sales also declined continuously.

**Factors establishing causal link**

110. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.
- i. There is significant dumping of the subject goods from the subject country despite duties in force.
  - ii. The volume of dumped imports has increased significantly over the injury period.
  - iii. The volume of imports has also increased in relation to Indian consumption and production.
  - iv. The increase in dumped imports prevented the domestic industry to sell its goods in the market at remunerative prices and the subject imports continued to undercut the domestic prices.
  - v. Despite the increase in its costs over the period, the domestic industry was forced to sell its goods at low prices since the prices of the subject imports continued to remain low.
  - vi. Such low prices imports prevented price increases, which otherwise would have occurred, and depressed the prices of the domestic industry.
  - vii. As a result, the market share of the domestic industry declined while that of the imports has increased over the period.
  - viii. The production and sales volume of the domestic industry have declined over the injury period
  - ix. The domestic industry faced significant accumulation of inventories as it was unable to sell its product in the market.
  - x. The domestic industry has suffered losses and cash losses.
  - xi. The domestic industry is not able to earn sufficient returns on the investments made and it earned negative returns on its investment.

**K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

111. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation.
112. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
113. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority. Following disclosure statement, and their comments, the Authority has rechecked the determinations, and certain errors were discovered, and these have been corrected, and the same is provided in the table below:

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
1	Sadara Chemicals Company	***	***	***	***	20-30
	Any other	***	***	***	***	30-40

#### L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

##### L.1. Submissions by other interested parties

114. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- a. Imposition of duties is not in public interest as the domestic industry is not capable of catering to entire demand, making users dependent on imports.
- b. Imposition of duty would increase costs for downstream users, creating supply uncertainty, discouraging long-term contracts and investment, and limiting access to advanced materials and technology, thereby adversely affecting consumers.

Particulars	Unit	Calculation				
Polyol CIF Price \$1300						
If ADD per tonne taken as-	\$/MT	50	100	150	200	250
Price Including ADD	\$/MT	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550
Price Including ADD	Rs/MT	1,12,725	1,16,900	1,21,075	1,25,250	1,29,425
Landed price including ADD	Rs/MT	1,21,225	1,25,400	1,29,575	1,33,750	1,37,925
Contribution of Polyol to Foam Cost	Rs/MT	78,796	81,510	84,224	86,938	89,651
Net Contribution adjusting for Yield Loss	Rs/MT	98,495	1,01,888	1,05,280	1,08,672	1,12,064
Foam per mattress	Kg	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
Cost Contribution	Rs	1,202	1,243	1,284	1,326	1,367
Cost of Polyol ADD	Rs/MT	41	83	124	165	207

per mattress						
Impact on retail sale	Rs	124	248	372	496	620

Particulars	Unit	Calculation				
If ADD per tonne taken as-	\$/MT	300	350	400	450	500
Price Including ADD	\$/MT	1,600	1650	1,700	1,750	1,800
Price Including ADD	Rs/MT	1,33,600	1,37,775	1,41,950	1,46,125	1,50,300
Landed price including ADD	Rs/MT	1,42,100	1,46,275	1,03,220	1,54,625	1,58,800
Contribution of Polyol to Foam Cost	Rs/MT	92,365	95,079	97,793	1,00,506	1,03,220
Net Contribution adjusting for Yield Loss	Rs/MT	1,15,456	1,18,848	1,22,241	1,25,633	1,29,025
Foam per mattress	Kg	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
Cost Contribution	Rs	1,408	1,449	1,491	1,532	1,573
Cost of Polyol ADD per mattress	Rs	248	290	331	372	414
Impact on retail sale	Rs	745	869	993	1,117	1,241

- c. Imposition of duties on FSP subsequent to recommendation of duties on TDI would cause a huge burden on the downstream users, which the MSME users cannot absorb.
- d. The applicant has underestimated the impact of proposed duties by considering a Rs. 20,000 mattresses, which does not reflect the price realities of the mainstream Indian mattress segment.
- e. Majority of mattresses, particularly those produced by MSMEs, fall within the 6,000 to 8,000 price range and for this segment, even a moderate increase in the cost of FSP would result in increased costs.
- f. The downstream industry largely constitutes of MSME manufacturers. While Sheela Foam claimed that there are 20-25 major manufacturers, there was no reference as to the nature of such enterprises.
- g. The vulnerability of MSMEs to sudden increases in input costs is recognized through the MSMED Act.
- h. The applicant cannot demand that MSMEs demonstrate actual closures before their adverse impact is acknowledged.
- i. While the petitioner relies on "Make in India" policy to justify protection for its own operations, it simultaneously disregards the same when it comes to the MSME-dominated downstream sector.

- j. The imports are necessary to meet the demand-supply gap as the domestic industry does not have capacity to cater to the existing demand in the country.
- k. Imposition of anti-dumping duty is not in public interest as it would sharply increase the production costs of the user industry, squeeze already thin margins, and risk losses, production cuts, or shutdowns across downstream sectors.
- l. Downstream manufacturers already face high cost from duty on key inputs, making additional duty on FSP unsustainable.

## L.2. Submissions by the domestic industry

115. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- a. Imposition of duties will have a negligible impact on the cost of downstream users and end users. For a mattress priced at Rs. 20,000, imposition of duties to the extent of current duties would have an impact of only 0.63%. Further, with respect to mattress of Rs. 6,000, the impact would be only 0.71%.

Price of one mattress	₹/u	A	20,000	6,000
Weight	KG/u	B	30	10
FSP consumed in 1 mattress	KG/u	C	6	2
Current price of FSP	₹/KG	D	98	98
Cost of FSP in 1 mattress	₹/KG	$E = D * C$	589	196
Current duty on FSP	\$/MT	F	253	253
Current duty on FSP	₹/KG	$G = (F * 84.27) / 1000$	21	21
Impact of proposed ADD	₹/kg	$H = G * C$	126	42
Impact of proposed add	%	$I = H / A$	0.63%	0.71%

- b. The total impact of proposed duties on FSP and TDI, major raw materials for foam, would be only 2.4%. For a mattress of Rs. 6,000, the total impact of the proposed duties would be only Rs. 144 per mattress.
- c. The impact of duties calculated on behalf of users is highly inflated as it relies on inaccurate CIF price, applicable customs duty and consumption factor. Further, the impact has been calculated on the margin of the users and not the cost of such users.
- d. The foam industry is a passthrough industry and the impact of imposition of duties would invariably be passed on to the mattress industry.
- e. Imposition of duties would be not be disadvantageous for the users as even after imposition of duties, the import price would still be lower than the normal value in the domestic market of the subject countries.
- f. The profitability of the users have not been impacted by imposition of duties on imports from other countries.
- g. While the users are claiming themselves to be MSMEs, certain users have earned bumper profits, which is more than double the revenue that the domestic industry is able to gain from sales of the product.
- h. Contrary to its claims, the Users' Association has not provided details regarding its members, number of members that are in the MSME sector or consumption share of such MSME producers in the total consumption.
- i. An increase in prices will not impact the demand of the product since the demand for FSP remained significant even when the prices were high in 2021-22.

- j. The domestic industry is currently in the process of expanding its capacity, which is currently under threat. There is a need to protect the sole producer of the subject goods in the country.
- k. Contrary to the claim that imports are necessary to meet the demand-supply gap, the dumped imports are entering the market in excess of any demand-supply gap.
- l. It has been a well settled principle that imports are inevitable where there is a demand-supply gap, but the same cannot be a justification for dumping.
- m. While the domestic industry is seeking re-establishment of fair market conditions, the users are demanding availability of imports at unfair prices. If the operations of users cannot survive based on imports at fair prices, it underlines the inefficiency of their operations.
- n. The product can be imported from other countries like Japan, Korea, Singapore, Taiwan and United States and at fair prices from the subject countries.
- o. Propylene oxide is majorly used in production of FSP by the applicant and non-imposition of duties will adversely impact the viability of propylene oxide operations as well.
- p. Non-imposition of duties will force the applicant to permanently shut down operations for FSP and shift to other products.
- q. Non-imposition of duties will make users completely reliant on subject imports creating a monopoly of the subject imports. In such a situation, the exporters can take advantage of the monopoly situation and exploit the users in order to maximize profits.

### **L.3. Examination by the Authority**

- 116. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
- 117. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
- 118. The domestic industry has emphasized that the imposition of duty does not restrict imports but only ensures fair prices. Even otherwise, the subject goods are also produced in a number of non-subject countries, such as Singapore USA, Japan, Korea. Therefore, the users are free to source the subject goods from the domestic industry and from other countries at competitive prices.
- 119. The other interested parties have argued that the domestic industry has underestimated the impact of proposed duties by considering a Rs 20,000 mattresses, whereas majority of mattresses fall within Rs 6,000 to 8,000. Contrary to this, the domestic industry has submitted that the imposition of duties will have a negligible impact of 0.6% for a mattress priced at Rs 20,000 and 0.71% for a mattress priced at Rs 6,000. Therefore, in either of the case, the impact of the duties will be negligible on the prices of the mattresses.

120. The Authority has noted the submissions made by all parties. The Association has submitted that 12.2 kg of the product under consideration is consumed per piece of mattress. Considering the import price of US \$ 1300, it implies that the product under consideration constitutes about 20% of the mattress price sold for Rs. 6000 (and 15% for a mattress sold for 8000). The Authority, therefore, finds that if the cost on account of the product under consideration is only 15-20% for a mattress, a 10%, 20% or 30% increase in the price shall be in the region of only 1.5%-6%. Further, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and the interested parties have not provided evidence showing increase in the price of the product under consideration as a result of imposition of the present anti-dumping duties. Table below shows impact of price increase in a mattress sold for Rs. 6000.

Particulars	Unit	Remarks	Value
CIF Price of Polyol	US\$/MT	A	1,300
Net contribution of polyol in foam	Rs./kg	$B = (A * \text{Exchange rate}) / 1000$	95
Foam used per mattress	Kg	C	12.2
Cost of polyol in a mattress	Rs./kg	$D = C * B$	1,160
Price of mattress	Rs.	E	6,000
Share of polyol in a mattress	%	$F = D / E$	19%
Impact of 10% ADD on price of mattress	%	$F * 10\%$	1.9%
Impact of 20% ADD on price of mattress	%	$F * 20\%$	3.8%
Impact of 30% ADD on price of mattress	%	$F * 30\%$	5.7%

121. Having examined the information submitted by domestic industry and the interested parties, the Authority notes that imposition of the anti-dumping duty would have a negligible impact on the downstream users.
122. Some interested parties have contended that the imports are inevitable due to the demand-supply gap in India and they would be forced to pay higher price for the imports. The Authority notes that the demand-supply gap is not a justification for dumping in India. Even if there is a demand-supply gap in the country, it is necessary that the product is available at fair prices. The imposition of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at the fair prices. In fact, the re-establishment of fair competition in the market may encourage further investment, which would help further bridge the demand-supply gap. Further, it is noted that the domestic industry has provided evidence in the form of project report, permission from Government of Gujarat allowing the domestic industry to set up production facility in Gujarat, and investor presentations referring to expansion and has submitted that the domestic industry is currently in the process of expanding its capacities in the state of Gujarat, and would be able to cater to a larger segment of the market share once these capacities are online.
123. Public interest comprises both consumer interests and producer interests, both of which are important and relevant. No doubt consumer interests are highly relevant, particularly in the case of final consumption of goods. However, producer interests are equally relevant, if not more. Producer interests became especially

significant during once-in-a-lifetime crises such as the COVID-19 pandemic. Therefore, it is essential that producer interests are given due consideration alongside consumer interests, if not greater importance.

124. The Authority further notes that imposition of duties is necessary to protect the investments made by the domestic industry. The domestic industry has claimed that it has undertaken significant expansions which needs to be protected by the adverse impact of dumping. Non-imposition of duties will force the domestic industry permanently shut down its operations for FSP and shift to other products. Therefore, the imposition of duties is necessary to protect the operations of the domestic industry and viability of the investments made.
125. The domestic industry has also emphasized that propylene oxide is majorly used in the production of subject goods and rely on the local production of subject goods. Therefore, non-imposition of duties will adversely impact the viability of the operations of the propylene oxide industry.

### **M. POST-DISCLOSURE COMMENTS**

126. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 5th March 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these parties in these final findings to the extent deemed relevant. Submissions regarding past history of duties, lack of backward integration, impact of cyclone, impact of other imports on the domestic industry and existence of demand-supply gap in the country, are reproduction of the previous submissions and which have been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

#### **M.1. Submissions by the other interested parties**

127. The other interested have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:
- a. The product produced by the domestic industry is inferior in terms of quality and technical characteristics. It contains higher potassium residue, which is not a minor variation and directly affects processability for downstream users, which are largely MSME.
  - b. The Authority has disregarded the fact that the potassium residue is significantly high in the product produced by KOH technology which renders the product completely unusable for consumption in polymer polyol. Limited use by some customers under adjusted process conditions cannot justify inclusion of technologically distinct products within a single product scope.
  - c. There are significant differences in the import volumes reported by the Authority for 2021-22 in the previous investigations and in this investigation.
  - d. The basis for key conclusions such as demand, market share, price undercutting and injury has not been disclosed appropriately in the disclosure statement.
  - e. The Authority has failed to address the fact that the technical data sheet submitted by the applicant relates to viscoelastic polyether polyol, and not FSP, which warrants clarification.
  - f. The Authority has failed to calculate the impact of imposition of duties on foam manufacturers and have simply calculated impact on mattresses as a simple percentage-of-retail-price exercise. Further, impact of duties should be seen in light of existing duties on TDI.
  - g. The downstream industry operates on limited margins and slightest increase in the cost of a major raw material can impact margins and affect commercial viability.
  - h. Merely because the applicant is expanding capacities which may become operational in the future, the users cannot be asked to bear present cost increases.
  - i. Considering the ongoing geopolitical disruption in the Middle-East region, the imports from Saudi Arabia are already disrupted and imposition of duties would add to the burden.

- j. The duty should be based on the injury margin of the present case and duty determined in the past should not be continued as it is, particularly in view of the fact that the costing methodology for determination of raw material cost has changed for the domestic industry.
- k. The normal value for Sadara Chemicals is highly inflated and must be revised.
- l. Participation by Dow Chemical International Private Limited must be duly recognised.
- m. The sales channel determined for Sadara is incorrect and must be revised.

### **M.2. Submissions by the domestic industry**

128. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

- a. The documentary evidence submitted on record clearly demonstrate that the applicant has made significant investment and is seriously committed to expanding its production capacities, which would help bridge the demand-supply gap.
- b. Continuation of duties will protect the applicant from permanently shutting down its operations and significant investments made to bridge the demand-supply gap.
- c. The possible impact of duties calculated based on the lowest price of mattress is not accurate as mattresses are offered at various prices in the market. Impact of duties considering various prices of mattresses will also be negligible.
- d. The total raw material cost has been calculated disregarding the cost of raw material purchased which accounts for significant share in the total raw material consumed.
- e. The utility cost has been erroneously determined by considering the cost of utility consumed at only 1 plant, while applying the consumption factor for the other plant. The utility cost should be revised by considering the consumption factor for the plant whose cost has been considered.

### **M.3. Examination by the Authority**

129. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations of submissions which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
130. Certain interested parties have reiterated their request for exclusion of FSP produced using DMC catalyst technology. The parties have repeated their submission claiming that the product produced by the domestic industry, using KOH catalyst route is inferior in quality and the higher potassium residue of the same makes the product entirely unusable for the downstream users. It has been claimed that the exporters in the subject countries are producing the product using DMC catalyst technology and thus, the users are forced to import in absence of supply of good quality product in the market.
131. The Authority has carefully examined the submissions and evidence provided by both sides. It is noted that the arguments regarding differences in the product produced by the domestic industry (KOH catalyst product) and that imported from other countries (DMC catalyst product) were raised before the Authority in the previous investigations as well. However, the Authority finds that no additional justification has been presented in the current investigation to support the exclusion sought or warrant a departure from the conclusions reached in the previous investigations.
132. Further, the Authority notes that the domestic industry has continued to supply the product to users in the market, who are also importing the subject goods. Thus, it is evident that the users are purchasing and using the products produced by the domestic industry and that imported from the subject countries interchangeably. In view of the same, exclusion of product produced using DMC technology is not warranted.

133. The domestic industry has claimed that the non-injurious price should be revised on account of raw material and utility cost. In this regard, it is noted that the raw material rates for PUC (including captively produced raw material) are determined based on the best-utilized production capacity and optimisation of raw material usage over the injury period as per guidelines contained in the Annexure III of the Anti-Dumping Duty Rules. Similarly, best utilisation of utility over the injury period is considered for determination of non-injurious price. Further, necessary adjustments have been made based on the verification carried out by the team and replies furnished by Domestic Industry.
134. With regards to the argument that the impact of duties should not be calculated with respect to mattresses alone, it is noted that none of the interested parties have submitted information on record which would allow the Authority to determine the impact of duties on any other downstream product. Further, the domestic industry as well as the Users' Association have also quantified impact with respect to mattresses only. In absence of any other information on record, the Authority does not find merit in this argument.
135. The other interested parties have argued that the impact of duties should be considered having regard to the fact that anti-dumping duties have also been imposed on other key raw material, namely TDI. The Authority has considered the submissions of parties. It is noted that the anti-dumping duty of upto US\$ 344.33 per MT has been imposed on imports of TDI. Considering the same, it is noted that the cumulative impact of duties on FSP and TDI would only be in the range of 2.4% with respect to mattresses.

Particulars	Unit	Remarks	Value
CIF Price of Polyol	US\$/MT	A	1,300
Net contribution of polyol in foam	Rs./kg	B	95
Foam per mattress	kg	C	12
Cost of polyol in a mattress	Rs./kg	$D = C*B$	1,160
Price of mattress	Rs	E	6,000
Share of polyol in a mattress	%	$F = D/E$	19%
Impact of 10% on price of mattress	%	$G = F*10\%$	1.9%
Impact of 10% on price of mattress	Rs./kg	$H = G/E$	116
Duty on TDI	Rs./kg	$I = (344.33*83.50)/1000$	29
Total impact on price of mattress	Rs./kg	$J = H+I$	145
Total impact on price of mattress	%	$K = J/E$	2.4%

136. With regards to the argument that duties should be revised for Sadara Chemicals based on the facts of the present case, it is noted that normal value, export price and landed price of Sadara has been worked out after examining the response of the cooperating producer and exporter, and all these parameters were shared with Sadara in the disclosure statement, The Authority has rechecked all calculations, and corrections have been made with respect to the landed value, and the same is mentioned in the relevant headings of this final findings.
137. It has also been argued that the normal value for Sadara Chemicals should be revised. in this regard, it is noted that the normal value is determined taking into account the response filed by sadara, and as per relevant anti-dumping rules.
138. With regards to the sales channel of the cooperative exporter, the same has been corrected in the relevant headings of this final findings.

139. With regards to the submissions that volume of the import quantified by the Authority is incorrect, it is noted that volume of imports mentioned by the Authority in the injury examination pertain to country wise import volume as per DG systems data. In fact import volumes for all years in the injury period have been taken from the DG systems data.
140. Following the comments to the disclosure statement, the Authority has acknowledged receipt of importers questionnaire by DCIPL (I) Ltd within the time limit.
141. With regard to comments from SABIC about re computation of net export price and landed value, the Authority has rechecked all calculations, and it is noted that while the net export price has been correctly computed as per rules, however, the landed value determination has been corrected.

## **N. CONCLUSION**

142. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
  - i. The product under consideration is Flexible Slabstock Polyol, having molecular weight of 3000-4000.
  - ii. The product under consideration includes product produced using KOH route and DMC catalyst route, in view of the similarity in the technical and physical properties of the end-product produced using both routes. Further, the product produced using both routes is used interchangeably in end-applications.
  - iii. The domestic industry has produced like article to the imported product under consideration.
  - iv. The application for initiation of the sunset review of anti-dumping duty was filed by Manali Petrochemicals Limited.
  - v. The applicant is the sole producer of subject goods in the country accounting for 100% of the total Indian production, and has been considered eligible to constitute domestic industry.
  - vi. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject country is above de minimis level and is significant.
  - vii. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period.
  - viii. The domestic industry has continued to suffer injury, despite anti-dumping duties in force, as a result of the subject goods which is evident from the following.
    - a. The volume of imports continued to increase over the injury period, in absolute and relative terms, and were the highest in the period of investigation.
    - b. The volume of imports has increased at a rate higher than the increase in demand in the country.
    - c. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
    - d. The landed price of subject goods has continued to decline over the injury period, and the delta of the landed price over the raw material cost of the domestic industry has declined, and has become negative.
    - e. The cost of sales of the domestic industry increased over the period, while the selling price of the domestic industry declined in response to the decline in the landed price of imports.
    - f. The market share of the domestic industry declined, while that of the imports increased.
    - g. The domestic industry has faced a decline in production and sales, despite a significant increase in demand.
    - h. The domestic industry was faced with significantly underutilized capacities.
    - i. The domestic industry was unable to dispose of its production, thereby resulting in the piling up of inventories.

- j. The domestic industry has supplied the subject goods at a price lower than its costs in order to compete with the imported goods.
  - k. The domestic industry faced significant losses and cash losses.
  - l. The return on capital employed of the domestic industry is negative.
  - m. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.
- ix. There is a likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of current anti-dumping duties, as evident from the following.
- a. The exporters in the subject country have continued to dump the goods despite duties in force.
  - b. The volume of imports has continued to increase in absolute and relative terms.
  - c. The volume of imports to India has increased at higher rate than increase in the exports to third countries, as seen from the response of the cooperative producer.
  - d. The imports are entering at prices which are likely to further suppress or depress the domestic prices.
  - e. The domestic industry has continued to suffer injury despite duties, and thus, is vulnerable to further injury.
  - f. The volume of imports has continued to increase in the post-POI period, while the landed price of imports has continued to decline.
- x. The injury margin for the subject country is positive.
- xi. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry.
- xii. Factors such as absence of backward integration are factors inherent to the domestic industry and have remained unchanged over the period, and thus, cannot have now caused injury to the domestic industry.
- xiii. The domestic industry segregated the impact of Michaung cyclone by reducing its available capacities. However, despite the same, the domestic industry has faced significant underutilization of capacities and decline in production.
- xiv. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports.
- xv. The imposition of anti-dumping duty is in the interest of the public and would have no adverse impact on the interests of public at large.
- xvi. Imposition of duties would result in negligible increase in the prices of the end-product and would not be a measurable burden for the end-consumers.
- xvii. The domestic industry has made significant investments in order to expand its production capacities and increase supply of its product in the market, as is evident from the supporting evidence and documents submitted showing the seriousness of commitment and investments made.
- xviii. Imposition of duties is necessary to protect the operations of the domestic industry and the viability of investments made.
- xix. Non-imposition of duties would also adversely impact the viability of operations of the upstream industry of propylene oxide.

#### **O. RECOMMENDATIONS**

143. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continuation / recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Having concluded that there is continuation of dumping and injury to the domestic industry and

likelihood of further injury if the anti-dumping measure are allowed to cease, the Authority is of the view that continued imposition of measures is necessary on imports of the product under consideration from the subject country. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive antidumping duty as notified vide final finding F. No. 6/20/2019-DGTR, dated 1st September 2020.

144. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject countries for a further period of five (5) years.

**Duty Table**

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39072910, 39072990	Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	150.06	MT	USD
2.	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any, other than that mentioned at S.N. 1	235.02	MT	USD
3.	-do-	-do-	Any country other than Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any	235.02	MT	USD

145. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of Flexible Slabstock Polyol sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct."

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

**P. FURTHER PROCEDURE**

146. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

AMITABH KUMAR, Authorized Officer